https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

प्रधानमंत्री की जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस यात्रा

वर्ष-12, अंक-12, 16-30 जून, 2017 (पाक्षिक) ₹20

भाजपा अध्यक्ष का अखंड प्रवास

भाजपा आदिवासियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है

प्रखर देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

1.17 करोड़ से अधिक लोगों का कौशल विकास

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के गुजरात एवं केरल प्रवास की तस्वीरें

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में वृक्षारोपण करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **मोदी सरकार और भाजपा आदिवासियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है: अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 31 मई को गुजरात के छोटा उदयपुर के देवलिया गांव में बूथ कमिटी मीटिंग और बोडेली गांव के श्री स्वामीनारायण मंदिर के प्रांगण में आदिवासी बंधुओं द्वारा आयोजित...

वैचारिकी

मध्यम वर्ग का मसीहा भारतीय जनसंघ 15

श्रद्धांजलि

प्रखर देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 17

लेख

किसान को राजनीति नहीं, समाधान चाहिए 18

भारत व भाजपा की आकांक्षा के प्रतीक नरेन्द्र मोदी 20

स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का बड़ा अभियान 22

सुधरती सत्ता, बिखरता विपक्ष 24

अन्य

जीएसटी को सुगमता से लागू करने हेतु केंद्र सरकार ने कई... 14

प्रधानमंत्री की जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस यात्रा 25

1.17 करोड़ से अधिक लोगों का कौशल विकास 29

2016-17 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात सबसे ज्यादा रहा 30

'स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ' अभियान की शुरूआत 31

'पूर्वोत्तर में पिछले 20 वर्ष में सबसे कम अलगाव की घटनाएं' 32

संगठनात्मक गतिविधियां

09 **'केरल में सच्चा स्वराज तब आयेगा, जब केरल की जनता को एलडीएफ और यूडीएफ से निजात मिलेगी'**

28 **भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित**

भाजपा किसान मोर्चा ने 8 जून को अपनी नयी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों...

सरकार की उपलब्धियां

12 **ग्रामीण योजनाओं में पिछले 3 वर्षों में 813 करोड़ व्यक्ति दिवसों का रोजगार सृजित किया गया**

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले तीन...

13 **रॉकेट जीएसएलवी मार्क-थ्री डी वन का सफल प्रक्षेपण**

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो ने 5 जून को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

आतंकवाद ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अपने ग्रह से आतंक की विभीषिका को नष्ट करने के लिए सभी मानवतावादी शक्तियां एकजुट हों।

@MVenkaiahNaidu

स्वच्छ भारत हमारे देश का सबसे बड़ा जनांदोलन है। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि महिलाएं इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

@rsprasad

तीन तलाक़ नारी गरिमा, सम्मान और न्याय का विषय है। इस पर सोनिया, ममता और मायावती जैसे महिला नेत्री क्यों चुप हैं?

@JPNadda

जम्मू एवं कश्मीर में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना से वर्तमान की 500 सीटों के अतिरिक्त 500 सीटें और बढ़ जाएंगी।

facebook

भाजपा का आतंरिक लोकतंत्र जब तक मजबूत है, इस देश के लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आ सकती। भारतीय जनता पार्टी में नेता जाति, वंश अथवा धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कृतित्व, परिश्रम, मेधा और परफॉरमेंस के आधार पर बनते हैं। — **अमित शाह**

हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। आज हर ग्राम पंचायत में आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, शारदे बालिका छात्रावास सहित अन्य नवाचारों से प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार आया है और इसका असर परीक्षा परिणामों में भी दिखाई दिया है। — **वसुंधरा राजे**

इसरो के वैज्ञानिकों को जीएसएलवी- एमकेIII डी1/ जीसैट-19 मिशन की सफलता के लिए बधाई! इसरो ने देश के सबसे ताकतवर और अब तक के सबसे भारी उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 को लांच कर दिया है। जीएसएलवी मार्क-3 को श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से शाम 5.28 बजे प्रक्षेपित किया गया। इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण द्वारा चार टन श्रेणी के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की दिशा में भारत के लिए नए अवसर खुल गए हैं। — **त्रिवेन्द्र सिंह रावत**

व्यंग्य चित्र

साभार: प्रेमिक जागरण

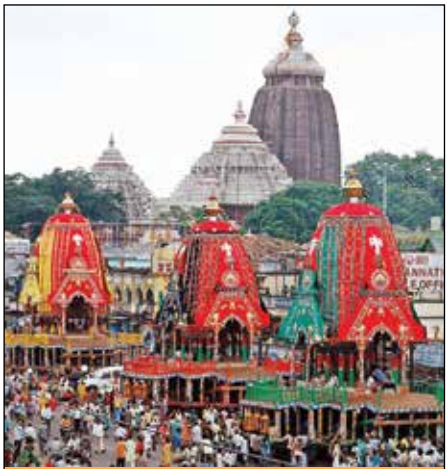

'कमल संदेश' की ओर से
सुधी पाठकों को
जगन्नाथ यात्रा
की हार्दिक शुभकामनाएं!

पाथेय

हमको ऐसी व्यवस्था निर्मित करनी होगी, जिसमें आदमी को रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए गलत रास्ते पर नहीं जाना पड़े। भयंकर अकाल के कारण अपनी भूख मिटाने के लिए गंदी जंगली चीज़ें न खाना पड़े। ऐसी स्थिति न आये इसकी चिंता करनी पड़ेगी। जनता में भी एक दूसरे की सहायता करने का प्रयत्न करना, यह भावना लानी होगी। नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा निर्मित करनी होगी।

-कुशाभाऊ ठाकरे

भाजपा अध्यक्ष का अखंड प्रवास

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह अपने राष्ट्रव्यापी प्रवास में विभिन्न प्रदेशों में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सहयोगी दलों, बौद्धिक वर्ग, पार्टी समर्थकों एवं आमजन से मिल रहे हैं। अपने इस अथक एवं अखंड प्रवास से उन्होंने राजनैतिक सक्रियता का एक नया मानदंड स्थापित किया है। इससे एक ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ है जब हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक लक्ष्यों के लिए संगठनात्मक प्रतिबद्धता के साथ कठोर परिश्रम करने के लिए स्वयं को समर्पित करने को तत्पर हुआ है। भुवनेश्वर में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने अध्यक्षीय संबोधन में अमित शाह ने निरंतर मिलती चुनावी जीत से संभावित आलस्य के निर्माण के प्रति आगाह करते हुए संगठनात्मक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 'परिश्रम की पराकाष्ठा' करने का आह्वान किया था। उन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, बल्कि स्वयं अपने 95–दिवसीय विस्तारक प्रवास एवं 15–दिवसीय विस्तृत प्रवास की घोषणा भी की। नेतृत्व के उच्च मानदण्डों को स्थापित करते हुए उन्होंने अनवरत् कठोर परिश्रम एवं अनुकरणीय राजनैतिक सक्रियता का उदाहरण हर कार्यकर्ता के सामने प्रस्तुत किया है।

भाजपा को जन–जन से अपार समर्थन मिल रहा है और इसकी चुनावी जीत भारतीय राजनीति के पूरे परिदृश्य को परिवर्तित कर रही है। जिस प्रकार का भारी जनसमर्थन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को मिल रहा है उससे पार्टी से जन–जन की जुड़ी आकांक्षाओं का पता चलता है। यह केवल एक नए भारत के निर्माण का अवसर नहीं बल्कि देश के कोने–कोने में पार्टी को सुदृढ़ करने का समय है ताकि पार्टी जनाकांक्षाओं पर खरी उतर सके। भाजपा अध्यक्ष इस बात पर निरंतर जोर देते रहे हैं कि जब पार्टी के पास नरेन्द्र मोदी के रूप में विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है, तब यही वह समय है जब उसे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक संगठनात्मक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। उनके शब्दों में यह एक ऐतिहासिक अवसर है और हर कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि इस अवसर का लाभ पार्टी को प्राप्त हो। पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष में जहां अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके नाम पर एक विस्तारक योजना का भी शुभारंभ हुआ है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पं. दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना का स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं तथा बूथ स्तर तक घर–घर जाकर व्यापक जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा वे बूथ समिति सदस्यों के साथ बैठकें, उनके घरों पर भोजन तथा विस्तारकों के साथ चर्चा एवं संवाद कर रहे हैं। अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम में श्री अमित शाह मंडल स्तर तक के पार्टी पदाधिकारी, विभिन्न विभागों एवं प्रकल्पों एवं पार्टी की गतिविधियों पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय बौद्धिक वर्ग के बीच पार्टी के विचार एवं कार्यक्रमों को रखकर अमित शाह ने बुद्धिजीवियों के साथ संवाद का एक नया दौर शुरू किया है। यह एक बहुत बड़ा व्यापक जनसंपर्क अभियान है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं ही विभिन्न स्तरों पर लोगों से संवाद एवं संपर्क स्थापित कर बूथ स्तर तक संगठन में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं।

संगठन के महत्व को समझते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने अथक प्रयासों एवं अटूट निष्ठा से इसे मजबूती से स्थापित करने के लिए स्वयं को समर्पित किया है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चला और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक दल बना उससे उनकी राजनैतिक इच्छाशक्ति का पता चलता है। प्रशिक्षण अभियान से हर कार्यकर्ता आवश्यक विधाओं से सुसज्जित हुआ है तथा वैचारिक समझ एवं राजनैतिक दृष्टि का उन्नयन हुआ है।

अपने अनगिनत नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बलिदान एवं साधना के फलस्वरूप आज भाजपा एक राजनैतिक विकल्प के रूप में उभरी है। यह सब पार्टी कार्यकर्ताओं के अटूट निष्ठा के कारण संभव हुआ है, जिन्होंने इस राष्ट्रयज्ञ में अपनी आहुतियां दी। आज यह आवश्यक है कि संगठन का और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हो, ताकि यह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक प्रभावी साधन बन सके। संगठन के महत्व को समझते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने अथक प्रयासों एवं अटूट निष्ठा से इसे मजबूती से स्थापित करने के लिए स्वयं को समर्पित किया है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चला और भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल बना उससे उनकी राजनैतिक इच्छाशक्ति का पता चलता है। प्रशिक्षण अभियान से हर कार्यकर्ता आवश्यक विधाओं से सुसज्जित हुआ है तथा वैचारिक समझ एवं राजनैतिक दृष्टि का उन्नयन हुआ है। अमित शाह के प्रवास का सुबह से लेकर देर रात तक का हर एक मिनट का सदुपयोग संगठन द्वारा किया जा रहा है। उनके अनवरत एवं अथक प्रयासों एवं अखंड प्रवास से वे एक सक्रिय अध्यक्ष के रूप में उभरे हैं जो आने वाले लंबे समय तक भाजपा को पंचायत से पालिर्यामेंट तक स्थापित करने को कृतसंकल्पित है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

मोदी सरकार और भाजपा आदिवासियों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 31 मई को गुजरात के छोटा उदयपुर के देवलिया गांव में बूथ कमिटी मीटिंग और बोडेली गांव के श्री स्वामीनारायण मंदिर के प्रांगण में आदिवासी बंधुओं द्वारा आयोजित गोष्ठी को संबोधित किया और गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी की दो-तिहाई बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। विदित हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय दौरे पर गुजरात पर थे। ज्ञात हो कि चार लाख से अधिक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती कार्य विस्तारक योजना के तहत 15 दिन, 6 महीना और एक साल के लिए देश भर में पूर्णकालिक के रूप में बूथ-स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करने को निकले हैं। अकेले गुजरात में लगभग 48 हजार कार्यकर्ता इस योजना के तहत बूथ-स्तर पर भाजपा को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।

श्री शाह ने अपने गुजरात दौरे की शुरुआत छोटा उदयपुर के आदिवासी गांव देवलिया गांव की जहां उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने घर-घर जाकर जनसंपर्क किया, घरों के दरवाजों पर स्टीकर चिपकाए और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की तीन साल की उपलब्धियों और गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं पर बुकलेट भी बांटे। श्री शाह ने गांव के कई घरों में भी गए जहां आदिवासी महिलाओं ने उनकी आरती उतारी और स्वागत किया। अध्यक्ष जी ने मोबाइल से मिस्ड कॉल के जरिये कई आदिवासी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। इसके बाद श्री शाह ने गांव में आयोजित बूथ कमिटी मीटिंग में भाग लिया और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ-स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। बूथ कमिटी मीटिंग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने हर बूथ को भाजपा का मजबूत गढ़ बनाने की अपील की।

बूथ कमिटी मीटिंग में बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तो मजबूत है ही, लेकिन यह हमारे लिए विश्राम का नहीं बल्कि और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती कार्य विस्तारक योजना से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और भाजपा फिर से सत्ता में आयेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों को लेकर घर-घर जाएं और हर बूथ को भाजपा का मजबूत गढ़ बनाने के लिए जुट जाएं। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की 120 सीटें थी, अब तो वे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब गुजरात में हमारी 150 सीटें आयेंगी।

बूथ कमिटी मीटिंग के पश्चात श्री शाह ने पार्टी कार्यकर्ता एवं देवलिया गांव के बूथ प्रमुख श्री पोपट भाई ईश्वर भाई राठवा जी के निवास पर दोपहर का भोजन किया। इसके बाद वे छोटा उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र बोडेली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्री स्वामीनारायण

मंदिर के प्रांगण में आदिवासी बंधुओं के गोष्ठी कार्यक्रम 'आदिवासी आगेवान मिलन समारोह' को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न एनजीओ, साधु-संतों और आदिवासी समुदाय के लगभग 500 प्रतिनिधि शामिल हुए।

श्री शाह ने कहा कि जब कांग्रेस का शासन था, तब आदिवासी क्षेत्र में न तो बिजली थी, न पानी की व्यवस्था थी, न सड़कें थीं और न ही स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था थी। गुजरात को कांग्रेस राज्य में मिला तो केवल कर्फ्यू और हिंसा। उन्होंने कहा कि जब 2001 से गुजरात में श्री नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार आई तो हर घर को 24 घंटे बिजली मिली, पाठशालाएं बनी, शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, समुचित स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाई, यह मोदी जी के नेतृत्व वाली गुजरात की कहानी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को एक कर्फ्यू-मुक्त राज्य बनाने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के कल्याण एवं विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गुजरात में अब तक मोदी जी के नेतृत्त्व में भाजपा सरकार ने 1 लाख

आदिवासी समाज भारतीय समाज एवं संस्कृति का गहना है, जिसको संरक्षित करने की जरूरत है और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस दिशा में कई कार्य किये हैं। राज पीपला में एक आदिवासी संग्रहालय बनवाया गया।

17 हजार 575 एकड़ जमीन आदिवासियों को सुपुर्द किया, जबकि कांग्रेस के समय गुजरात के आदिवासी किसी भी लाभ से वंचित थे। उन्होंने कहा कि PESA योजना के माध्यम से गुजरात सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि आदिवासी क्षेत्र में वन संपत्तियों की बिक्री से होने वाली आय को ग्राम पंचायत के माध्यम से आदिवासियों के ही विकास में काम आये।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी समाज भारतीय समाज एवं संस्कृति का गहना है, जिसको संरक्षित करने की जरूरत है और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस दिशा में कई कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि राज पीपला में एक आदिवासी संग्रहालय बनवाया गया, आदिवासियों छात्रों के लिए 6 होस्टल बनवाये गए और 15 लाख आदिवासी छात्रों के लिए भोजन और यूनिफ़ॉर्म की व्यवस्था की गई। आदिवासियों के कल्याण के लिए 485 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई और लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि वाली ग्राम सड़क योजना में से लगभग 4800 करोड़ रुपये की राशि आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटित किये गए। उन्होंने कहा कि 2004 में श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों के लिए योजनायें बनाने और सुविधाएं देने की पहल शुरू की जो अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत दाहोद और तापी में एक-एक मेडिकल कॉलेज बनवाया गया।

बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन, अकोटा (वड़ोदरा)

'कांग्रेस को केवल अपनी अगली पीढ़ी की चिंता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदीजी को देश की अगली पीढ़ी की चिंता है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों के 110 दिवसीय विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत अपने एक दिवसीय गुजरात प्रवास में 31 मई को अकोटा (वड़ोदरा) के सर सयाजीराव नगर गृह में बुद्धिजीवियों के साथ कई विषयों पर चर्चा की और उनसे भारतीय जनता पार्टी के साथ मन से जुड़ने की अपील की।

श्री अमित शाह ने कहा कि 10 सदस्यों के साथ शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ सदस्यों की संख्या के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जन संघ को जीत मिलती थी तो वह अखबारों की सुर्खियां बनती थी। आज देश के विभिन्न राज्यों में हमारे 1387 विधायक हैं और 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, साथ ही 4 राज्यों में भाजपा एवं सहयोगी दलों की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि कभी देश की संसद के अंदर हमारे केवल दो सदस्य हुआ करते थे, आज संसद में हमारे लगभग सवा तीन सौ सांसद हैं और पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का मान-सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है।

पार्टी के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश में सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टियों का अकाल पड़ गया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मैं दो प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सिद्धांत से मतलब है देश के लिए बनने वाली सभी नीतियों पर पार्टी के पास स्पष्ट दृष्टिकोण का उपलब्ध होना और उस दृष्टिकोण के आधार पर देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से अपना पक्ष रखना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी दल या फिर क्षेत्रीय पार्टियां – उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। उनके पास देश के लिए कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गठन तो देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए किया गया था, वह तो आजादी को प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हेकिल भर थी, उसकी कोई विचारधारा ही नहीं थी, वह कभी सिद्धांतों के आधार पर चली ही नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई विचारधाराओं वाले लोग थे और उन सब के पास कोई सिद्धांत नहीं था, केवल किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था, इसलिए बाद में इससे

कई पार्टियां अलग-अलग समय पर बाहर निकलती चली गई।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद देश में 70 सालों तक जो सरकारें चली हैं उसमें से एक तो कांग्रेस की सरकार है जो लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में रही हैं। कई राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें भी रही हैं, कुछ समय तक केंद्र में और कई राज्यों में प्रादेशिक दलों की सरकारों ने भी शासन किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देश में केंद्र और राज्यों में चली हैं। उन्होंने कहा कि देश ने चारों प्रकार की सरकार देखी है - कांग्रेस की विचारधारा, कम्युनिस्ट की विचारधारा, परिवारवाद व जातिवाद की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर चलने वाली सरकारें देखी है। प्रबुद्ध जनों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अब देश में तुलनात्मक अभियान करने का समय आ गया है। चारों प्रकार के विकास के मॉडल देश की जनता के सामने है, उनके विकास के आंकड़े जनता के सामने उपलब्ध हैं - यह देखना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों में क्या विकास हुआ है, कम्युनिस्ट की राज्य सरकारों में कैसा विकास हुआ है, परिवारवाद व जातिवाद के आधार पर चलने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारों के राज्य में कैसा विकास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कैसा विकास हुआ है। उन्होंने कई राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह कांग्रेस सरकारों, कम्युनिस्ट दलों की सरकारों और क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने राज्य के विकास को बाधित कर उसे काफी पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहीं। वहां हमने विकास के नए मापदंड स्थापित किये और उस राज्य के इतिहास में डेवलपमेंट की नया अध्याय जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस के एक नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, वह सरकार लोकाभिमुख सरकार होती है, पारदर्शी सरकार होती है, निर्णायक सरकार होती है और लोक-कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार होती है।

श्री शाह ने कहा कि 2012 के समय को याद कीजिये, जब देश में कांग्रेस-नीत यूपीए का शासन था, देश के युवाओं में गुस्सा और आक्रोश था, महिलायें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी, आये दिन हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता रहता था। सेनाओं का अपमान होता था, हमारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर देश का पक्ष रखने जब जाते थे तो कहीं चर्चा भी नहीं होती थी, देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता थी, अर्थव्यवस्था के सारे मापदंड नीचे चले थे, नीतिगत फैसले नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में देश की जनता ने देश के बेहतर भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्ति करते हुए उनके हाथों में देश की बागडोर सौंपने का काम किया। उन्होंने कहा कि 2014-2017 के इस सफ़र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई कहानी लिखी है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को अटल जी के समय 8.4 से 4.4% पर लाकर छोड़ा, हम फिर से इन तीन सालों में विकास दर को 7.6% तक लाने में सफल हुए हैं और यह लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये आज हिन्दुस्तान ने दुनिया भर में यह संदेश दिया है कि अब हमारी सीमाओं की ओर कोई बुरी नजर से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि इससे यह संदेश गया कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन सीमाओं पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चाहे देश की विदेश नीति की बात हो या रक्षा नीति की या फिर आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई की बात हो, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, भारत से अच्छे रिश्ता बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के विकास व गरीब-कल्याण के लिए लगभग 106 योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी एक वर्ग के लिए बनी हो। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की प्लानिंग एक अद्भुत विकास के मॉडल पर किया गया है जो सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी है। ■

'केरल में सच्चा स्वराज तब आयेगा, जब केरल की जनता को एलडीएफ और यूडीएफ से निजात मिलेगी'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 2 जून को कल्लूर में केरल के चुने गए भाजपा जन-प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित किया और उनसे राज्य में भाजपा की मजबूत नींव डालने की अपील की। इस बैठक में स्थानीय निकाय से लेकर देश की संसद में केरल की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए 1200 से अधिक जन-प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष ने केरल भाजपा के इनिशिएटिव जल स्वराज वेबसाईट को भी लॉन्च किया। विदित हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत कल से तीन दिवसीय दौरे पर केरल में हैं। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने आज पार्टी की केरल इकाई के कोर ग्रुप की मीटिंग में लिया और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने केरल में एनडीए की सहयोगी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मेरे लिए यह बहुत ही आनंद का विषय है कि आज केरल में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1200 चुने हुए जन-प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि शायद मीडिया और कई लोगों को यह अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन मैं इन्हीं 1200 जन-प्रतिनिधियों में केरल में भारतीय जनता पार्टी सरकार का बीज देखता हूं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी केरल में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में जनता के सामने खड़ी है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केरल भारतीय जनता पार्टी इकाई पार्टी और पार्टी की विचारधारा के विस्तार के लिए अथक परिश्रम कर रही है। मुझे भरोसा है कि चार साल बाद केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।

श्री शाह ने कहा कि आज मैंने केरल भाजपा के इनिशिएटिव जल स्वराज वेबसाईट को लॉन्च किया है, लेकिन केरल भाजपा के हर कार्यकर्ता को यह संकल्प लेकर काम करना है कि केरल में सच्चा स्वराज तब आयेगा जब केरल की जनता को एलडीएफ और यूडीएफ से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है। उसको यदि ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार के संघर्षों से हर राज्य भाजपा इकाई निखर कर बाहर आई है। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि हम सिर्फ सत्ता के लिए काम करने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं हैं, बल्कि हम विचारधारा के लिए और देश के उत्थान के लिए काम करने वाली पार्टी हैं।

'भाजपा महज राजनीतिक दल नहीं, वरन एक वैचारिक आंदोलन है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय केरल प्रवास के दूसरे दिन 3 जून को त्रिवेंद्रम, केरल में समाज के विशिष्ट और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की बैठक को संबोधित किया और उनसे भारतीय जनता पार्टी के साथ मन से जुड़ने की अपील की। विदित हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय दौरे पर केरल में हैं। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने महान समाज सुधारक श्री अय्यंकली जी की प्रतिमा पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और केरल में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने जिला अध्यक्षों और जिला महासचिवों के साथ भी एक बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

श्री शाह ने कहा कि सभी पत्रकार एक सवाल बहुत उत्सुकता के साथ हमें पूछते हैं कि 10 सदस्यों से शुरू हुई भारतीय जन संघ आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज भाजपा के देश भर में 1387 विधायक हैं, 14 राज्यों में भाजपा की सरकार है, देश में 330 सांसद हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसके बावजूद आपको क्या चाहिए कि आप पूरे देश का दौरा करने

के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि देश भर में आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका लक्ष्य सरकार बनाना नहीं है, बल्कि भारत को विश्वगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करना है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में जय और पराजय के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है बल्कि यह एक वैचारिक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि इसी कारण देश में जिस-जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार चुन कर सत्ता में आती है, वहां-वहां जनता बार-बार भाजपा का ही चुनाव करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को वैभव के परम शिखर पर ले जाना चाहती है।

श्री शाह ने कहा कि 2014 लोक सभा चुनाव से पहले देश में हर तरफ निराशा का माहौल था। महिलायें असुरक्षित थीं, हमारी सीमाओं पर आये दिन अतिक्रमण होते रहते थे, दुनिया में देश का सम्मान नीचे जा रहा था, बेरोजगारी चरम पर थी, महंगाई आसमान छू रही थी, जीडीपी दर दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा था, सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस की सी स्थिति थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के उस वक्त केंद्र सरकार का हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को तो कोई प्रधानमंत्री समझता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की शासन-व्यवस्था श्री मनमोहन सिंह ने श्री मोदी जी को सौंपी थी, उस को रिपेयर करने में ही तीन साल लग जाने थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इन तीन साल के अंदर देश की स्थिति को बदलने में सफल हुए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यूपीए के शासन के समय देश की विकास दर 4.4% थी, इसे 7.1% तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, सेंसेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर पर है और भारत का विदेश मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च शिखर पर है।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश की 60% आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं था, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत तीन वर्ष में ही देश के लगभग 28.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए। उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट खोलने के बाद सरकार ने लाभार्थियों की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया, जिससे सरकार ने हजारों करोड़ रुपये की चोरी बचाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के पांच करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से लगभग दो करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी देश के लगभग 12 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में टॉयलेट्स तक नहीं थे, हमने तीन ही साल में साढ़े चार करोड़ टॉयलेट्स बनाने का काम ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने खुले में शौच से मुक्ति का मुहिम शुरू कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक के माध्यम से मोदी सरकार देश के 7.64 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी घरों में लाईट नहीं थी, टॉयलेट्स नहीं थे, गैस सिलिंडर नहीं पहुंचा था और मीडिया पूछती है कि अच्छे दिन आ गए? उन्होंने कहा कि जिस के घर में गैस का सिलिंडर पहुंचा है, जिस घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, जिस घर में बिजली पहुंची है, वहां अच्छे दिन जरूर आ गए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केरल के विकास के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाये हैं और केरल को विकास के लिए केंद्र से मिलने वाले फंड में काफी बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार के समय, जिसमें वामपंथी पार्टियां भी भागीदार थी, 14वें वित्त आयोग में केरल का सेन्ट्रल टैक्स में शेयर 33368 करोड़ रुपये का था, जबकि मोदी सरकार के 15वें वित्त आयोग में यह बढ़कर 98912 करोड़ रुपया हो गया है। उन्होंने कहा कि सोनिया-मनमोहन के यूपीए II ने केरल को ग्रांट-इन ऐड के रूप में 5476 करोड़ रुपये दिए थे जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए

यूपीए के शासन के समय देश की विकास दर 4.4% थी, इसे 7.1% तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है।

केरल को 17968 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए II के समय केरल को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में कुछ भी नहीं मिलता था, जबकि मोदी सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में केरल के लिए 9519 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के यूपीए II के समय केरल को लोकल बॉडीज ग्रांट के रूप में 2732 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए 15वें वित्त आयोग में 7683 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि केरल में हाईवे निर्माण के लिए 64 हजार करोड़ रुपये, डीप वाटर सीपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि और रेलवे के विकास के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावे स्मार्ट सिटीज के लिए 194 करोड़ रुपये, 9 अमृत सिटीज के लिए 2359 करोड़ रुपये, कोचीन मेट्रो के लिए 1257 करोड़ रुपये, 3632 हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो इरिगेशन के लिए 180 करोड़ और मछुआरों के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन हेतु 130 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने

कहा कि 70 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी केवल सेन्ट्रल ग्रांट में की गई है। उन्होंने कहा कि यदि इन सभी ग्रांट को जोड़ दिया जाय तो यह 150000 करोड़ रुपये का बजट बनता है। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जन-धन के माध्यम से केरल में लगभग 32 लाख लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए, मुद्रा योजना के तहत 19.59 लाख लोगों को 11 655 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराये गए, लगभग 2.27 लाख टॉयलेट्स बनाए गए और आज केरल में 2035 गांव ऐसे हैं जहां टॉयलेट्स बनाने का काम समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि केरल में लगभग एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये गए हैं।

'हिंसा से भाजपा की प्रगति को नहीं रोका जा सकता'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तीन दिवसीय केरल प्रवास के अंतिम दिन 4 जून को त्रिवेंद्रम में भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय की नींव रखी और राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं से केरल को भाजपा का मजबूत गढ़ बनाने का आह्वान किया। श्री शाह ने चेंकलचूला के बूथ संख्या 96 में स्थित पार्टी कार्यकर्ता श्री रतीश जी के निवास पर सुबह का नाश्ता किया। तत्पश्चात भाजपा अध्यक्ष ने चेंकलचूला के बूथ संख्या 95 में भारतीय जनता पार्टी पार्टी की बूथ कमिटी मीटिंग में भाग लिया और पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने समाज सुधार के लिए काम करने वाले कई वरिष्ठ लोगों को भी सम्मानित किया। बूथ कमिटी मीटिंग में भाजपा की वयोवृद्ध महिला कार्यकर्ता गोमती अम्मा भी पहुंची और उन्होंने कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया। श्री शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती कार्य विस्तारक योजना के तहत केरल में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने निकले पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक की और पार्टी के विस्तार एवं विचारधारा के प्रचार-प्रसार की रणनीति पर चर्चा की। ज्ञात हो कि भाजपा अध्यक्ष देश के सभी राज्यों के अपने 110 दिन के विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत तीन दिन के दौरे पर केरल में थे।

भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि किसी और पार्टी के लिए कार्यालय का महत्व ज्यादा हो या न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यालय के बिना चल ही नहीं सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर एवं संगठन की शक्ति के बल पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कार्यालय निर्माण कार्य प्रकल्प के तहत दिसंबर 2019 तक देश के हर जिले में एक सुव्यवस्थित कार्यालय बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा।

केरल में भारतीय जनता पार्टी एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं पर निरंतर हो रहे हिंसात्मक हमले और अत्याचार पर कड़ा प्रहार करते

हुए श्री शाह ने कहा कि केरल में जब-जब लेफ्ट पार्टी की सरकार आती है, तब-तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हिंसात्मक हमले बढ़ जाते हैं, अत्याचार बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार भी केरल में वामपंथी सरकार आने के बाद एक-के-बाद-एक भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के 13 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या राजनीतिक कारणों से वामपंथियों द्वारा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक खतरनाक और शर्म की बात यह है कि इसमें से अधिकतर हत्या केरल के मुख्यमंत्री के स्वयं के विधान सभा क्षेत्र और जिले में हुई है। उन्होंने कहा कि यदि यहां के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी यह समझती है कि हिंसा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को दबा दिया जाएगा तो वे गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पर जितना हिंसा और अत्याचार होगा, कमल उतना ही तेजी से खिल कर और निखर कर बाहर आयेगा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ये न सोचे कि केरल में उनकी सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले बच निकलेंगे। उन्होंने कहा कि हम क़ानून के रास्ते से यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने भी भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केरल में जिस प्रकार से वामपंथी सरकार ने हिंसा की राजनीति शुरू की है, मुझे विश्वास है कि केरल की शांतिप्रिय जनता हिंसा की राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी।

केरल के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम सब मिलकर केरल में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करें और केरल को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनाएं। उन्होंने कहा कि आज मैं इस बूथ कमिटी मीटिंग के माध्यम से पूरे केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप हर बूथ को मजबूत कर केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि गोमती अम्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर मैं अभिभूत हूं, अम्मा ने इतनी बड़ी आयु में कष्ट करके भी मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ■

ग्रामीण योजनाओं में पिछले 3 वर्षों में 813 करोड़ व्यक्ति दिवसों का रोजगार सृजित किया गया

28,000 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को वर्ष 2021 तक सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों (2014-17) के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण (पीएमए-जी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जैसी योजनाओं में 813 करोड़ व्यक्ति दिवसों से अधिक रोजगार के अवसर जुटाए हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान एमजीएनईआरईजीए के तहत 636.78 करोड़ व्यक्ति दिवस, विभिन्न योजनाओं के तहत 78 करोड़ व्यक्ति दिवस और पीएमएई के तहत 99 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार जुटाए गए। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (डीडीवाई-जीकेवाई) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 86,120 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 54,196 को रोजगार मिले। इसी तरह 2015-16 में लगभग 1,35000 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 2016-17 में 84,900 उम्मीदवारों को रोजगार मिले।

श्री तोमर ने कहा कि चालू वर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 5 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने तथा ऐसे 70 प्रतिशत युवाओं को वेतन और स्वसहायता रोजगार कार्यक्रमों में नियुक्ति देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि 2016-17 में स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) ने 4 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

श्री तोमर ने कहा कि मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1.23 करोड़ संपत्तियों को भू-टैग किया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र में डाल दिया गया है। लगभग 96% वेतन भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीबीटी प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों के खातों में जमा किया गया है। अभी तक 8.73 करोड़ कामगारों की आधार संख्याओं को एनआरईजीएसओफ्ट (एमआईएस) में सीडिड किया गया है और 4.73 करोड़ कामगारों को उनकी रजामंदी से आधार आधारित भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जॉब कार्ड का सत्यापन/उन्नयन किया गया है और 1 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड सत्यापन के बाद रद्द किए गए है।

पीएमए-जी के बारे में श्री तोमर ने कहा कि सरकार 2022 तक "सभी के लिए आवास" के लिए अपने उद्देश्य के अनुरूप सरकार 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। 2014-15 से 2015-16 के दौरान पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत 45.98 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले 34.82 लाख घरों का निर्माण किया गया है। 2016-17 के दौरान 32.14 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया गया है और इस पर 16,07 करोड़ रूपये खर्च हुए।

पीएमजीएसवाई के बारे में उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की गति बढ़कर 130 किलोमीटर के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गई है, जो पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक औसत वार्षिक निर्माण दर है। 2016-17 के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत 47,447 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे 11,641 बस्तियों से संपर्क स्थापित हुआ। 2016-17 के दौरान एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना के तहत 9 एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों के सबसे बुरी तरह प्रभावित 44 जिलों के साथ साथ और आसपास के जिलों में सभी मौसम के लिए सड़कों का निर्माण पर 11,725 करोड़ रुपये अनुमानित लागत के साथ शुरू किया गया है यह काम मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा।

श्री तोमर ने कहा कि पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार 2030 तक प्रत्येक घर में सतत आधार पर नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 'हर घर जल' का सपना नागरिकों की भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। देश में करीब 28,000 प्रभावित बस्तियों को मार्च 2021 तक सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन के शुभारंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय निर्धारित किया गया है और पेयजल और स्वच्छता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए धन देने में किसी भी राज्य के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

श्री तोमर ने कहा कि 14 वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ग्राम गांवों में वस्तुगत और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करने के लिए पंचायतों को 5 वर्षों के दौरान 2 लाख करोड़ रूपए अधिक जारी करेगी। इससे पहले 13वें वित्तीय आयोग ने पंचायतों को 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अभी तक राज्यों को 51,234 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके है और 44 लाख पंचायत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। ■

रॉकेट जीएसएलवी मार्क-थ्री डी वन का सफल प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो ने 5 जून को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र शार से देश के नये विकसित शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी मार्क-थ्री डी वन का सफल प्रक्षेपण किया और इसके ज़रिए उपग्रह जी सैट-19 को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया। जीएसएलवी मार्क-थ्री का यह प्रथम कक्षीय मिशन था, जिसका लक्ष्य पूरी तरह देश में निर्मित क्रायोजनिक ईंजन सहित, इस यान की क्षमता का मूल्यांकन करना था। - उपग्रह जी सैट-19 का भार वजन तीन हजार 136 किलोग्राम है। भारत की धरती से छोड़ा जाने वाला यह देश का सबसे भारी उपग्रह है।

सुचारू रूप से चली साढ़े पच्चीस घंटे की उल्टी गिनती के बाद, पहले से निर्धारित, भारतीय समय के अनुसार शाम पांच बजकर 28 मिनट पर सेकेंड लांच पैड से 640 टन भार के जीएसएलवी मार्क-थ्री का प्रक्षेपण मिशन प्रारंभ हुआ। इसके बाद उपग्रह के प्रक्षेपण का प्रमुख चरण शुरू हुआ। इंजन की कार्यक्षमता और स्थिति पूर्वानुमान के अनुसार सही सिद्ध हुई। प्रक्षेपण के करीब 16 मिनट बाद जीसैट-19 उपग्रह को सफलता पूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया।

सफल प्रक्षेपण पर प्रधानमंत्री ने इसरो को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसएलवी–एमकेIII डी-1/जीएसएटी-19 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, 'जीएसएलवी–एमकेIII डी-1/जीएसएटी-19 मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के समर्पित वैज्ञानिकों को बधाईयां। जीएसएलवी–एमकेIII डी-1/जीएसएटी-19 मिशन भारत को अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान और उपग्रह क्षमता के निकट ले जाता है। राष्ट्र को इस पर गर्व है।'

जीएसएलवी से पृथक होने के तत्काल बाद कर्नाटक में हासन स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने उपग्रह का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। जीसैट-19 एक उच्च प्रवाह-क्षमता वाला संचार उपग्रह है। जीएसएलवी मार्क थ्री डी-वन का प्रक्षेपण कई मायनों में खास है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का परिणाम है। इसरो ने जटिल क्रायोजनिक इंजन को स्वदेश में विकसित कर इतिहास रचा है।

आने वाले दिनों में जीसैट-19 की कक्षा को वर्तमान भूस्थिर अंतरण कक्षा से ऊंचा उठाते हुए इसकी अंतिम गोलाकार भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया जायेगा। इसके लिए विभिन्न चरणों में उपग्रह की लिक्विड अपोजी मोटर को फायर किया जायेगा। इस आपरेशन के अंतिम चरण में उपग्रह के सोलर पैनल और एंटीना रिफ्लेक्टर सक्रिय किए जाएंगे। निर्धारित स्लॉट में स्थापित होने और कक्षा में इसके पेलोड के सफल परीक्षणों के बाद उपग्रह की सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ■

जीएसटी लागू होने के बाद आम उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती होंगी

जीएसटी कानून के 01 जुलाई, 2017 से प्रभावी हो जाने के बाद निम्नलिखित वस्तुओं पर जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शून्य दर के साथ लागू होगा। इसके परिणामस्वरूप वस्तुएं आम आदमी को सस्ती मिलेंगी :

1. खाद्यान्न एवं आटा
2. मोटे अनाज
3. दालें
4. आटा
5. मैदा
6. बेसन

पंजीकृत ट्रेडमार्क वाली वस्तुओं को छोड़कर जिनके मामले में जीएसटी 5 फीसदी की दर से लगेगा।

1. ताजा दूध
2. ताजा सब्जियां एवं ताजे फल
3. मुरमुरा (मूरी)
4. सामान्य नमक
5. पशु चारा
6. कार्बनिक खाद
7. जलावन लकड़ी
8. कच्चा रेशम/कच्चा ऊन/जूट
9. हस्त संचालित कृषि उपकरण

इन वस्तुओं पर कुछ भी जीएसटी न लगने के कारण इनमें से ज्यादातर वस्तुओं की कीमतें इनके मौजूदा मूल्यों की तुलना में लगभग 4-5 फीसदी कम हो जाने यानी इस हद तक सस्ती हो जाने की आशा है। ■

जीएसटी को सुगमता से लागू करने हेतु केंद्र सरकार ने कई उपकरों को समाप्त किया

केंद्र सरकार ने पिछले तीन आम बजट 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में धीरे-धीरे वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले कई उपकरों को समाप्त किया, जिससे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 से सुगमतापूर्वक लागू करने की जमीन तैयार की जा सके। केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कई उपकरों को समाप्त करने का कदम उठाया, जिससे कई वस्तुओं एवं सेवाओं में जीएसटी के लिए विभिन्न कर स्तरों में इसे आसानी से समायोजित किया जा सके।

केंद्र सरकार ने अपने आम बजट 2015-16 में शिक्षा उपकर समाप्त किया, जिसमें कर योग्य सेवाओं पर लगने वाला माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर शामिल है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट दी।

अपने आम बजट 2016-17 में केंद्र सरकार ने सीमेंट, गत्ते पर उपकर समाप्त किया। तीन उपकरों (श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1976 में संशोधन कर लौह अयस्क खानों, मैगनीज अयस्क खानों और क्रोम अयस्क खानों पर उपकर) समाप्त किया। तंबाकू उपकर अधिनियम 1975 में संशोधन कर तंबाकू उपकर और चलचित्र श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1981 में संशोधन कर चलचित्र श्रमिक कल्याण उपकर समाप्त किया। केंद्र सरकार ने अपने आम बजट 2017-18 में अनुसंधान एवं विकास उपकर अधिनियम में संशोधन कर अनुसंधान और विकास उपकर समाप्त किया।

कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 के जरिए निम्नलिखित उपकरों को समाप्त किया गया, हालांकि इसे जीएसटी लागू करने की तारीख के साथ ही लागू किया जाएगा।

1. रबर अधिनियम 1947 - रबर पर उपकर
2. उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम 1951 - ऑटोमोबाइल पर उपकर
3. चाय अधिनियम 1953 - चाय पर उपकर
4. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 - कोयला पर उपकर
5. बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1971 – बीड़ी पर उपकर
6. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 - कुछ उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल पर लगाया गया उपकर
7. चीनी उपकर अधिनियम 1982, चीनी विकास निधि अधिनियम 1982 – चीनी पर उपकर
8. जूट उत्पादक उपकर अधिनियम 1983 – जूट से निर्मित वस्तुओं या उत्पादन या जूट के हिस्से में उपकर
9. वित्त (2) अधिनियम 2004 – उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर शिक्षा उपकर
10. वित्त अधिनियम, 2007 – उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर
11. वित्त अधिनियम 2010 - स्वच्छ ऊर्जा उपकर
12. वित्त अधिनियम 2015 - स्वच्छ भारत उपकर
13. वित्त अधिनियम 2016 – बुनियादी ढांचा उपकर और कृषि कल्याण उपकर

हालांकि, जीएसटी लागू होने के बाद भी निम्न उपकर जारी रहेंगे, क्योंकि ये सीमा शुल्क या ऐसे सामान से संबंधित है जो जीएसटी के तहत नहीं आते हैं:

1. वित्त (2) अधिनियम 2004 - आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर
2. वित्त अधिनियम, 2007 - आयातित वस्तुओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर
3. तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 के तहत कच्चे पेट्रोलियम तेल पर उपकर
4. मोटर स्पिरिट (सड़क उपकर) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
5. हाई स्पीड डीजल ऑयल (सड़क उपकर) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
6. मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
7. तंबाकू और तंबाकू उत्पाद और कच्चे पेट्रोलियम तेल पर एनसीसीडी। ■

मध्यम वर्ग का मसीहा भारतीय जनसंघ

| दीनदयाल उपाध्याय |

जब से मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, पढ़े-लिखे लोग समाज को शोषित और शोषक अथवा छोटे और बड़े दो वर्गों में बांटने के आदी हो गए हैं। विचारों की यह रूढ़ि हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। अगर कभी बरबस हमें उस समाज को भी देखना पड़े, जो न शोषक है और न शोषित अथवा जो कभी शोषण का शिकार होता है और दूसरे ही क्षण स्वयं शोषक बन जाता है, तो हमारे मार्क्सवादी भाई उसे महत्त्वहीन कहकर टाल देते हैं। किंतु यह महत्त्वहीन नहीं, कम-से-कम हिंदुस्थान में तो यह अत्यंत ही महत्त्व का है। कारण, यह संख्या और क्रिया दोनों ही दृष्टि से सबल रहा है। यह बहुत बड़ा वर्ग मध्यवर्ग के नाम से पुकारा जा सकता है, यदि हम वर्गों के रूप में ही विचार करें। मार्क्सवादी इस वर्ग का रोल अभी तक निश्चित नहीं कर पाए हैं। एक दशक पूर्व तक वे इसे शोषण का एक पुर्जा मात्र मानकर शोषक की श्रेणी में डालते थे' किंतु अब वे सिद्धांत में उसे 'शोषित, पर व्यवहार में शोषक' ही मानते हैं। इस वर्ग के महत्त्व को न समझने के कारण मार्क्सवादी न तो इनकी समस्या को समझ पाए हैं और न उसका कोई हल ही उनके पास है।

जिस देश में बड़े-बड़े उद्योगों का बाहुल्य नहीं है, वहां मध्यम वर्ग की बहुतायत होती है। भारत में तो ऐसा ही है। यूरोप के देशों के विपरीत यहां करोड़पति और निर्धन के बीच करोड़ों व्यक्ति हैं, जो अधिक धनी नहीं तो बिछल गरीब भी नहीं कहे जा सकते। यही वर्ग भारत के सामाजिक जीवन का सृष्टा, उसके सांस्कृतिक विकास का जनक तथा राष्ट्रीय आंदोलन का अगुआ रहा है। यह मध्यम वर्ग ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। इस वर्ग का बल ही राष्ट्र का बल है। हमारी परंपरा भी इसी वर्ग का आधार लेकर आगे बढ़ी है। इस वर्ग में सभी प्रकार के लोग सम्मिलित हैं। किसान, मज़दूर, व्यापारी, कर्मचारी, अध्यापक, लेखक, राजनीतिज्ञ, जमींदार और छोटे-छोटे पूंजीपति आदि सभी व्यवसायों के व्यक्ति मध्य वर्ग में आते हैं। भारत की अर्थनीति का यह मज़बूत पाया रहा है।

भारतीय अर्थनीति मध्यम वर्ग को केंद्र-बिंदु मानकर चली है। अतः यहां उन बड़े-बड़े कल-कारखानों की गुंजाइश नहीं, जिनमें आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण एक व्यक्ति के हाथों या कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो जाता है तथा जन सामान्य एक यंत्र का पुर्जा मात्र बनकर शोषण का शिकार होता है। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने पर भी स्थिति में विशेष अंतर नहीं आता, बल्कि आर्थिक व राजनीतिक दोनों ही शक्तियों का केंद्रीकरण होने से हालत बदतर हो जाती है। अतः भारतीय जीवन प्रणाली छोटे-छोटे उद्योगों के विकास की कल्पना लेकर चली। इन उद्योगों में मालिक और मज़दूर भिन्न नहीं होते और यदि कहीं हों तो भी उनमें इतना पारस्परिक संबंध रहता है कि वे एक इकाई ही हो जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से तथा उसके आधार पर सामाजिक दृष्टि से यहां बड़े और छोटे दो वर्ग नहीं, बल्कि मध्य वित्त वर्ग की बहुलता है।

मध्य वित्त वर्ग की स्थिति में पिछले 150-200 वर्षों में अंतर आया है। प्रथम तो ईस्ट इंडिया कंपनी की अमलदारी में, जब यहां के उद्योग-धंधे नष्ट किए गए तो बहुत से कारीगर तथा व्यापारी बेकार हो गए। उनमें से कुछ तो दूसरे-दूसरे पेशों में लग गए तथा कुछ नष्ट हो गए। कारीगर तो खेती आदि की ओर झुके तथा व्यापारियों ने विदेशी माल का कारोबार प्रारंभ कर दिया। उद्योग-धंधों के नष्ट हो जाने के कारण मध्यवर्ग के लोगों की संख्या में कमी हुई। फिर भी वे काफ़ी थे। उनमें से अधिकांश के जीवन-यापन के साधन छिन चुके थे। अंग्रेजों ने उन्हें नए साधन देने का प्रयत्न किया। किंतु यह विष मिली हुइ रोटी थी। इसने उसका पेट तो भरा किंतु नए रोग पैदा कर दिए। अंग्रेज़ी काल में नौकरी मध्यवित्त व्यक्तियों का प्रधान व्यवसाय रह गई। अकबर इलाहाबादी के शब्दों में- 'बीए. हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए', यही हमारे जीवन की कहानी रह गई। इस कहानी का नायक बनने के लिए अंग्रेज़ी पढ़ना ज़रूरी था, अंग्रेज़ीदां ही नहीं अंग्रेज़ी तहज़ीबयाफ्ता भी होना चाहिए था। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारा समाज से संबंध टूट गया। हम अपनी परंपरा से बिछुड़ गए। फलतः जोहड़ के पानी के समान इस समाज में गंदगी बढ़ी, जिसका व्यक्तिकरण अनेक सामाजिक और मानसिक समस्याओं के रूप में हुआ। राम मोहन राय से लेकर आज तक के सभी महापुरुषों ने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की। महर्षि दयानंद, तिलक, विवेकानंद, रामतीर्थ, डॉ. हेडगेवार आदि ने परंपरा से संबंध स्थापित करने का प्रत्यक्ष स्पष्ट प्रयत्न किया और अन्यों ने नई भूख पैदा करके कुछ पश्चिमी और कुछ भारतीय ढंग का मिला-जुला भोजन देकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न किया।

भारतीय अर्थनीति मध्यम वर्ग को केंद्र-बिंदु मानकर चली है। अतः यहां उन बड़े-बड़े कल-कारखानों की गुंजाइश नहीं, जिनमें आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण एक व्यक्ति के हाथों या कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो जाता है।

अंग्रेज़ी शिक्षा के परिणामस्वरूप हमारी प्रवृत्ति बहिर्मुखी हो गई। साथ ही आजीविका के लिए कलम का सहारा ही प्रमुख होने के कारण हम वीणापाणि के पवित्र संदेश को भूल गए। हमारी रीति, नीति, विचार, व्यवहार किसी का भी संबंध गांवों में फैले करोड़ों लोगों से न रहा। अंग्रेजों ने इस विभेद को सब प्रकार से बढ़ाया ही। यहां तक कि सन्

1935 के विधान में तो हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी, अपितु शहरी और देहाती इलाकों के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र परिसीमित हुए।

सभ्यता और संस्कृति के इस खोखलेपन के साथ ही धीरे- धीरे आर्थिक दिवालियापन भी घर कर गया। नौकरियों में तो निश्चित संख्या तक लोग ही लिए जा सकते हैं। फलतः पढ़े-लिखे बेकारों की संख्या दिन-पर-दिन बढने लगी। दफ्तरों के सामने 'जगह नहीं है' की पट्टियां लग गईं। बढ़ती हुई स्मस्या को देखकर आंसू पोछने के लिए 'सपू कमेटी' बनाई, किंतु उनकी सिफारिशों पर कभी अमल नहीं किया गया।

द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने पर यह समस्या अस्थायी रूप से सुलझ गई। नौकरियों की बहुतायत हो गई। यद्यपि पुराने कर्मचारियों के सामने महंगाई के कारण नई समस्याएं आ खड़ी हुईं, किंतु कई नौकरयां मिल जाने के कारण बेकारी को राहत मिली। बाहर से चीज़ें आना बंद हो जाने के कारण स्वदेशी उद्योग भी पनपे। फलतः एक नए मध्य वर्ग का सृजन हुआ, जो पढ़ा लिखा तो नहीं था किंतु आर्थिक दृष्टि से उसकी स्थिति पढ़े-लिखे मध्य वर्ग से कहीं अच्छी थी। हां, कंट्रोल के कारण व्यापारियों को, विशेषकर छोटे व्यापारियों को अवश्य धक्का लगा। फिर भी आर्थिक दृष्टि से समस्या भीषण नहीं थी।

महायुद्ध समाप्त होने तथा स्वराज्य के बाद चक्र फिर से पुरानी दिशा में घूमने लगा है। यदि हमने इस बदली हुई स्थिति को समझा होता तथा आगे आने वाली समस्याओं को रोकने का प्रयत्न किया होता तो आज हालत अच्छी होती, किंतु हमने अपनी अदूरदर्शी नीति से समस्या को और भी विकट बना दिया है। आज मध्यम वर्ग की अत्यंत विषम स्थिति है। इसका हम संक्षेप में यह विश्लेषण कर सकते हैं।

प्रथम तो ऐसा पढ़ा-लिखा वर्ग है, जो यदि नौकरी में है तो उसका वेतन बहुत ही अपर्याप्त है। उसकी समस्याएं कुछ तो स्वाभाविक हैं तथा कुछ नए ज़माने के विचारों तथा पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण से बढ़ गई हैं। इनकी पूर्ति के लिए वेतन की कमी अनेक भ्रष्टाचारी साधनों से पूरी की जाती है, जिसका परिणाम दिन-प्रतिदिन नैतिक पतन में हो रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी वर्ग है, जो पढ़ा-लिखा है किंतु बेकार है। उसके पास जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं। घर की पूंजी खर्चीली पढ़ाई-लिखाई में स्वाहा हो गई, कलम छोड़कर हाथ का काम कर नहीं सकते। फलतः उसके मन में निराशा घर करती जा रही है। तीसरा वर्ग ऐसा भी है, जो अभी तक बेकार नहीं, जो हाथ का कारीगर है, काफ़ी कमाता है किंतु आज संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से वह काफ़ी पीछे है। यह नया मध्यवित्त वर्ग है किंतु अभी आर्थिक और सामाजिक जीवन में अंतर है। हमें एक ओर इन सभी की समस्या को सुलझाना है तो दूसरी ओर यह प्रयत्न करना है कि मध्यवित्त वर्ग अधिकाधिक बढ़े न कि थोड़े दिनों में बेकार होकर पीछे हट जाए।

दुर्भाग्य से शासन की नीति इस वर्ग को बढ़ाने की अपेक्षा घटा ही रही है। प्रथम तो उसकी उद्योग नीति में ऐसे उद्योगों को कोई स्थान नहीं, जिन्हें थोड़ी पूंजी से तथा थोड़े ज्ञान से चलाया जा सकता है। जो कुछ छोटे-छोटे उद्योग लड़ाई के काल में पनपे थे, वे नष्ट हो रहे हैं। आयात-निर्यात की नीति इन स्वदेशी उद्योगों के लिए हानिकर रही है। विदेशी पूंजीपति भ्रष्ट नौकरशाही को सहज ही अपने अनुकूल कर लेते हैं, जिससे भारत के उद्योगों के हित के प्रतिकूल आयात किया जाता है। निर्यात पर लगाए गए टैक्सों ने हमारे छोटे-छोटे ही नही बड़े उद्योगों को भी आघात पहुंचाया है। कर नीति भी मध्यम वर्ग को समाप्त कर रही है। बहुसूत्री बिक्री कर का परिणाम बिचौलियों को समाप्त कर रहा है। फैक्टरी ऐक्ट तथा श्रमिकों संबंधी जो कानून बनाए गए हैं, उन्हें छोटे-छोटे कारखानों पर भी इस प्रकार लागू किया जाता है, जिसमें न तो श्रमिकों का लाभ होता है और न उद्योगों का। सरकारी क़ानूनों के मातहत कागजी कार्रवाई तथा भ्रष्टाचार ने उत्पादन व्यय इतना बढ़ा दिया है कि छोटे-छोटे उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। नियंत्रण से भी सबसे अधिक धक्का मध्य वित्त लोगों को ही लगा है। उसका व्यवहार भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हित में तथा खुदराफ़रोशों को घातक ही होता है। पंचवर्षीय योजना में भी इस बेकारी को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

भारत की समस्या का हल प्रथम तो शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन कर बेकारों को शिक्षित करना है। आवश्यकता है कि उन्हें टेक्निकल शिक्षा दी जाए। जो डिग्रियां ले चुके हैं, उन्हें भी थोड़े दिनों की कोई ट्रेनिंग देकर उत्पादन के योग्य बनाया जा सकता है। उनको केवल शिक्षा देने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि इस प्रकार शिक्षा प्राप्त नवयुवकों की सहकारी समितियां बनाकर उनसे छोटे-छोटे उद्योग प्रारंभ करवाए जाएं। इनके माल के विपणन का भी प्रबंध सरकार को करना होगा। यदि इस प्रकार व्यापक रूप से छोटे-छोटे धंधे खुलवाए जाएं तथा उनको शहरों मे केंद्रित करने के बजाय गांवों में विकेंद्रित किया जाए तो देश की आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समस्या भी सुलझ जाएगी। गांव और शहरों के बीच की खाई ही इस समस्या की जड़ में है। उसे मिटाना ही होगा। बिना पढ़ा किंतु आर्थिक दृष्टि से कमाऊ वर्ग के लिए हमें शिक्षा एवं समाज केंद्रों की स्थापना करनी होगी। इन केंद्रों में पढ़े और अनपढ़ सबके मिलन की व्यवस्था करनी आवश्यक है। 4 रुपए रोज़ कमाने वाला रिक्सा वाला यद्यपि 72 रुपए के बाबूजी से आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, किंतु अभी ऐसा कोई अवसर नहीं, जहां दोनों समान भूमि पर मिल सकें। एक ओर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगों की संस्कृति और सभ्यता की गलत धारणा को बदलना होगा तो दूसरी ओर अनपढ़ को भी सुसंस्कृत बनाना होगा।

भारतीय जनसंघ यद्यपि निचली श्रेणी के लोगों की ओर से आखें बंद नहीं करता, फिर भी वह मध्य वित्त वर्ग की समस्या को देश की प्रमुख समस्या मानता है। आज के करोड़ों किसान-मज़दूर, छोटे तथा उजड़े हुए जमींदार, कर्मचारियों आदि के सामने की समस्याओं को समन्वित रूप से सुलझाया जाए तभी देश का कल्याण होगा। स्वदेशी के व्यापक प्रसार, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय एवं टेक्निकल शिक्षा तथा गांव-गांव और मुहल्लों-मुहल्लों में समाज केंद्रों की स्थापना से यह संभव हो सकेगा। ■

- पांचजन्य, दिसंबर 31, 1952

प्रखर देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

(6 जुलाई, 1901-23 जून, 1953)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान शिक्षाविद, चिन्तक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतवर्ष की जनता उन्हें एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में जानती है। देश के लाखों लोगों के मन में उनकी गहरी छवि अंकित है- एक प्रखर देशभक्त की। वे आज भी आदर्श हैं- बुद्धजीवियों और मनीषियों के। वे आज भी समाए हुए हैं- लाखों भारतवासियों के मन में एक पथ-प्रदर्शक एवं प्रेरणापुंज के रूप में।

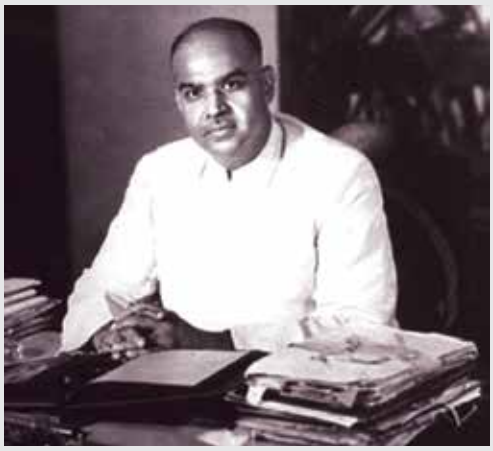

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उनके ज्ञान, प्रतिभा और स्पष्टवादिता के कारण उनके मित्र और विरोधी सभी उनका आदर करते थे।

डॉ. मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को एक प्रसिद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के एक जाने-माने व्यक्ति थे। डॉ. मुखर्जी ने कलकत्ता से स्नातक डिग्री प्राप्त की। वे 1923 में सीनेट के सदस्य (फैलो) बन गये। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन् 1924 में कलकता उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में नाम दर्ज कराया। बाद में वे सन् 1926 में 'लिंकन्स इन' में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर बन गए।

वे तैंतीस वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे कम उम्र के कुलपति बने और सन् 1938 तक इस पद पर आसीन रहे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद् के सदस्य चुने गए, लेकिन उन्होंने अगले वर्ष इस पद से उस समय त्यागपत्र दे दिया, जब कांग्रेस ने विधानमंडल का बहिष्कार कर दिया था। बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए।

जब वर्ष 1937-41 में कृषक प्रजा पार्टी-मुस्लिम लीग गठबन्धन सत्ता में आया, वे विरोधी पक्ष के नेता बन गए। वे फजलुल हक के नेतृत्व में प्रगतिशील गठबन्धन मंत्रालय में वित्त मंत्री के रूप में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने एक वर्ष से कम समय में ही इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वे हिन्दुओं के प्रवक्ता के रूप में उभरे और शीघ्र ही हिन्दू महासभा में शामिल हो गए। सन् 1944 में वे इसके अध्यक्ष बनाए गए।

पंडित नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। डॉ. मुखर्जी ने लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के मुद्दे पर 6 अप्रैल, 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरू गोलवलकर जी से परामर्श करने के बाद 21 अक्तूबर, 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की नींव रखी और वे इसके पहले अध्यक्ष बने।

सन् 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ ने संसद की तीन सीटें जीतीं, जिनमें से एक सीट पर श्री मुखर्जी जीतकर आए थे। उन्होंने संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनायी, जिसमें 32 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्य सभा से थे, हालांकि जिसे अध्यक्ष द्वारा एक विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई।

डॉ. मुकर्जी जम्मू-कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था, वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। डॉ. मुखर्जी ने जोरदार नारा बुलंद किया कि - एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।

संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉ. मुकर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत से काटने की साजिश रची जा रही है। पंडित नेहरू ने डॉ. मुखर्जी पर ही संदेह व्यक्त कर दिया। कोई भी समझौता अथवा रास्ता दिखाई न देने पर डॉ. मुखर्जी ने बिना परमिट जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने का फैसला कर लिया। उनकी इस घोषणा में देश की अखंडता के लिए बलिदान देने की उमंग स्पष्ट झलकती थी।

9 मई, 1953 को प्रातः 6.30 बजे डॉ. मुखर्जी रेलगाड़ी से अपने साथियों, जिनमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, के साथ जम्मू के लिए रवाना हुए। परंतु जब वे अपने साथियों सहित जम्मू की सीमा रावी नदी के किनारे लखनपुर पहुंचे तो कश्मीर मिलिशिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 23 जून, 1953 को संदिग्ध परिस्थितियों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई है। सच तो यह है कि डॉ. मुखर्जी ने भारत विरोधी, विघटनकारी और पाकिस्तानपरस्त शक्तियों से लोहा लिया। वे भारत मां के मुकुट कश्मीर को पाकिस्तानी शिकंजे में जाने से रोकने में सफल हुए। अखंड भारत के लिए वीरगति प्राप्त करने वाले शहीद डॉ. मुखर्जी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि भारत की जनता और नेता एकजुट होकर पूरी ताकत से देशद्रोहियों का प्रतिकार करें तो विदेश प्रेरित शक्तियां अवश्य परास्त होंगी। ■

किसान को राजनीति नहीं, समाधान चाहिए

एम. वेंकैया नायडू

कांग्रेस पार्टी फिर आग में घी डालने के अपने पुराने खेल पर लौटकर बेचैनी पैदा करने की कोशिश कर रही है। जैसी इसकी आदत है, यह मध्यप्रदेश के मंदसौर में किसानों के हिंसक आंदोलन के दौरान गोलीबारी में छह लोगों के मारे जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का राजनीतिक फायदा उठाने में लगी है।

यह बहुत दुख की बात है कि हिंसा में लोगों की जान गईं। जहां केंद्र में एनडीए सरकार और भाजपा किसानों की चिंताओं पर गौर कर रही है, विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ऐसे दर्शा रही है जैसे कृषक समुदाय को एनडीए के सत्ता में आने के बाद ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पांच दशकों तक अपने राज के दौरान किसानों की उपेक्षा करने के बाद उनके बारे में बात करने का क्या कांग्रेस को कोई हक है? सच तो यह है कि किसानों की दशा यूपीए की लगातार दो सरकारों के दशक भर के शासन के दौरान खराब हुई, जब किसानों की आत्महत्याएं अत्यधिक बढ़ीं और कृषि में वृद्धि दर दो फीसदी से भी नीचे गिर गई। किसानों की समस्याओं का इस तरह राजनीतिकरण क्या खुला अवसरवाद नहीं है? सभी दलों को संकुचित राजनीतिक फायदों से परे जाकर स्थिति को सामान्य बनाने में मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार का समर्थन करना चाहिए। दुर्भाग्य से भड़की हुई भावनाएं शांत करने की बजाय राजनीतिक दल ठीक इसके विपरीत चल रहे हैं। अन्यथा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दौड़कर मंदसौर पहुंचने की कोई कैसे सफाई देगा? जाहिर है उन्हें लगता है कि यह उन्हें मीडिया में आने का मौका देगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसा भड़कने पर भी उन्होंने यही

जहां केंद्र में एनडीए सरकार और भाजपा किसानों की चिंताओं पर गौर कर रही है, विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस ऐसे दर्शा रही है जैसे कृषक समुदाय को एनडीए के सत्ता में आने के बाद ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

करने का प्रयास किया था। इसी तरह वे जेएनयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 'सांस्कृतिक कार्यक्रम' और विरोध प्रदर्शन के बाद वहां पहुंच गए थे, जहां देश को बांटने और आतंकियों को महिमामंडित करने वाले नारे लगाए गए थे।

यह सही है कि विभिन्न राज्यों से कृषि ऋण माफ करने की मांग की जा रही है लेकिन, निश्चित ही यह दीर्घावधि का समाधान नहीं है, क्योंकि इससे किसानों को अस्थायी राहत ही मिलती है। इसका एक ही समाधान है कि कृषि में लगने वाली चीजों की लागत पर नियंत्रण रखकर कृषि उपज की वाजिब कीमतें सुनिश्चित करना। सच तो यह है कि आरबीआई गर्वनर ने कृषि ऋण माफ करने के खिलाफ आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि यदि राज्यों के पास इसकी वित्तीय गुंजाइश नहीं है तो पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय अनुशासन से हमने जो कुछ भी हासिल किया है, वह खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही यह साफ कर दिया है कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं हैं। वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए कई किसान हितैषी पहल की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान की फसल के बीमा की दिशा में सबसे बड़ा योगदान है। इसमें न्यूनतम प्रीमियम के तहत अधिकतम मुआवजा देने की बात है और यह योजना सभी मौसम की सभी फसलों को दायरे में लेती है। 50,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। करीब 7.1 करोड़ सॉइल हैल्थ कार्ड जारी किए गए हैं और लक्ष्य सभी 14 करोड़ किसानों को ये कार्ड जारी करने का है। ई-नाम के जरिये किसान सारे कृषि बाजारों से जुड़ जाएगा और जहां अच्छा भाव मिले उपज वहां बेच सकेगा। सरकारी कदमों के कारण दलहनों का उत्पादन बढ़ा है। 2016-17 में अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,625 से बढ़ाकर 5,050 रुपए, उड़द 4,625 से बढ़ाकर 5,000 और मुंग 4,850 से बढ़ाकर 5,250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। रबी फसलों का समर्थन मूल्य भी काफी बढ़ा दिया गया है। इस साल बजट में खेती के कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ रखे गए हैं। खेती में आने वाली नई टेक्नोलॉजी और नवीनतम जानकारियों से किसानों को वाकिफ कराने के लिए दूरदर्शन ने खास किसान चैनल शुरू किया है।

गोलीबारी में पांच लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा मांगना कांग्रेस की दीवालिया सोच बताता है। यहां यह बताना मौजूं होगा कि मध्यप्रदेश के ही बैतूल जिले के मुलताई में दिग्विजय सिंह के शासन (1998) में गोलीबारी से 24 किसान मारे गए थे। तब तो सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था। क्या कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा मांगा था? क्या सोनिया गांधी वहां गई थीं? वास्तविकता तो यह है कि मध्यप्रदेश में चौहान के रूप में अब अत्यधिक किसान हितैषी मुख्यमंत्री है। उनके फोकस के कारण पिछले दो साल में राज्य में कृषि वृद्धि दर 20 फीसदी हो गई है। कृषि हित में उठाए कदमों में कृषि कर्ज पर शून्य प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, किसानों को बिजली पर 4,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी और कृषि क्षेत्र को करीब 10 घंटे अबाधित बिजली सप्लाई। सिंचाई क्षेत्र को 7.5 लाख हैक्टेयर से 40 लाख हैक्टेयर तक बढ़ा दिया गया है। सभी फसलों पर वाजिब दाम के लिए मध्यप्रदेश सरकार अब मूल्य स्थिरता निधि स्थापत करने वाली है। प्रदेश सरकार ने मालवा की नदियों में नर्मदा लाने का अनोखा कार्यक्रम शुरू किया है और क्षिप्रा के साथ नर्मदा को तो जोड़ भी दिया है। एक लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं। किसानों को सबसे बड़ा बीमा कवरेज दिया जा रहा है। रबी के लिए 4,060 करोड़ और खरीफ के लिए 4,416 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं।

मौजूदा समस्या अनाज, दलहन, प्याज और सोयाबिन में उत्पादन अधिक होने और बाजार में भाव मिलने से उपजा है। मुख्यमंत्री ने तो किसान संगठनों द्वारा रखी गई 13 में से 11 मांगें मान भी ली हैं। मुख्यमंत्री ने मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का

मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वे अवसरवादी नेताओं के बहकावे में आएं। किसानों की विभिन्न चिंताएं दूर करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। यह सोचना नादानी होगी कि इन्हें रातोंरात हल कर लिया जाएगा। गोदाम बनाने की बात हो, कोल्ड स्टोरेज चैन, रेफ्रिजरेटर वैन, बिजली, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वैल्यू एडिशन, किफायती समय पर कर्ज और बाजार की जानकारी तक पहुंच, कृषि से जुड़े सारे मसलों पर एनडीए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान की दशा सुधारने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

मुआवजा देने की घोषणा की है। मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वे अवसरवादी नेताओं के बहकावे में आएं। किसानों की विभिन्न चिंताएं दूर करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। यह सोचना नादानी होगी कि इन्हें रातोंरात हल कर लिया जाएगा। गोदाम बनाने की बात हो, कोल्ड स्टोरेज चैन, रेफ्रिजरेटर वैन, बिजली, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वैल्यू एडिशन, किफायती समय पर कर्ज और बाजार की जानकारी तक पहुंच, कृषि से जुड़े सारे मसलों पर एनडीए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान की दशा सुधारने और उनकी आय दोगुनी करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ■

(लेखक केंद्रीय नगर विकास मंत्री हैं।)

भारत व भाजपा की आकांक्षा के प्रतीक नरेन्द्र मोदी

डॉ. आर. बालाशंकर

अपने तीन वर्ष के शासनकाल के बाद नरेन्द्र मोदी को भारत के महानतम प्रधानमंत्रियों में शुमार किया जा रहा है। राजनैतिक दृष्टिकोण और मोदी का करिश्मा कोई सानी नहीं रखता है, परन्तु उन्होंने अपना स्थान इतिहास में सुनिश्चित कर लिया है क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र का गहन कायाकल्प किया है और अर्थव्यवस्था एवं डिप्लोमेसी को सम्पूर्ण रूप से प्रबंधित किया है।

विपक्षी लापता हो गए हैं, आलोचकों की जुबान बंद हो गई है और ओपीनियन पोल के अनुसार मोदी वर्ष 2019 में आराम से जीत जाएंगे। यह आकर्षक यात्रा 2014 से शुरू होने के बाद आज तक चलती जा रही है कि मोदी के आलोचक भी बदतर भ्रामक अवस्था में अपनी राह ढूंढने में असमर्थ दिखाई पड़ते हैं।

श्री मोदी एक ऐसे राजनैतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आए हैं कि जैसा कि इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और वी.पी. सिंह जैसे लोकप्रिय नेताओं के पास पहले से ही भारी जनादेश था, फिर भी वे अपने अर्ध-कार्यकाल में ही चमक खो दिए। ध्यान रहे कि श्री मोदी वे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात के 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे। वह गुजरात में लगातार तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में जीतते रहे और जब वे प्रधानमंत्री के लिए लड़े, तो उस राज्य ने लोकसभा में 26 सीटों में से 26 सीटें प्रदान की। तब से मोदी ने हर चुनाव जीता चाहे वह विधानसभा, उपचुनाव या पूरे देश में स्थानीय निकायों का चुनाव रहा हो, उसमें वे सफल रहे। बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव केवल एक अपवाद रहा और पिछले महीने की कार्पोरेशन की विजयों ने इस लगभग उस पूर्व पराजय को शून्य बना कर रख दिया है। यह एक ऐसा कारनामा रहा है जो विगत में देश में किसी अन्य राजनीतिज्ञ ने नहीं दिखा पाया है।

श्री मोदी इस प्रकार की विजय के 'शुभंकर' सिद्ध हुए हैं जबकि

श्री अमित शाह लड़ाई के अर्जुन सिद्ध हुए हैं। श्री मोदी की भारी लोकप्रियता ने बीजेपी को ऐसे राज्यों में भी सत्ता दिलाई, जहां कोई भी अपने बूते पर भाजपा शासन की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, यूपी और अरूणाचल शामिल हैं। यह ऐसी राजनीतिक विजय है जिसने विपक्षियों को बुरी तरह से असफल बनाकर रख दिया और श्री मोदी हर तरह से सफल रहे हैं।

श्री मोदी ने किस प्रकार से यह राजनीतिक पूंजी बनाई, यह बात उनके विरोधियों और आलोचकों को भी समझ में नहीं आ पा रही है। मोदी ने अपनी विश्वसनियता दो नारों के आधार पर तैयार की जिसका श्रेय 'गुड एकानॉमिक्स' और 'गुड पॉलिटिक्स' को जाता है, जिसे गरीबों के प्रति कायाकल्प करने की वचनबद्धता से निर्माण किया गया है। इससे वे अन्य लोगों की तुलना में अलग किस्म के राजनीतिज्ञ दिखाई पड़ते हैं। इन तीन वर्षों में मोदी गरीबों के मसीहा बन गए हैं। 'प्रधान सेवक' की भूमिका में उनका वादा और राष्ट्रीय कोष के एक-एक पैसे के संरक्षक के रूप में उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है।

इतने से थोड़े समय में कौन सा ऐसा कोई राजनीतिज्ञ रहा है जिसने 2 करोड़ परिवारों को निःशुल्क कूकिंग गैस कनेक्शन प्रदान किए? विगत में किसी भी अन्य सरकार ने 35 करोड़ भारतीयों के बैंक एकाउंटधारियों को समर्थ बनाया और उनमें से अधिकांश को निःशुल्क बीमा और बीमा आवरण प्रदान किया। पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना भारी हिट सिद्ध हुई। थोड़े से समय में ही साढ़े चार करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ और स्वच्छता एक लोकप्रिय राष्ट्रीय अभियान साबित हुआ। किसी भी अन्य सरकार ने इंफ्रास्टक्चर निर्माण के लिए चार लाख करोड़ का आवंटन नहीं किया। चाहे यह पोर्ट, ग्रामीण सड़कें, राजपथ, वाटरवेज या अन्य कोई कारगर कदम हो। इससे लाखों–लाखों दिलों के स्वप्न साकार हुए हैं।

श्री मोदी ने सफलतापूर्वक एक राजनीतिक एजेण्डा तैयार किया है। एक वर्ष की समाप्ति पर आज केरल सीपीएम सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया है, वह मोदी सरकार की कार्ययोजना की तरह पढ़ा जा रहा हैं। यही नहीं श्री मोदी ने विकास की राजनीतिक प्रतियागिता को बढ़ावा दिया है। मोदी ने राष्ट्रीय राजनीतिक की स्थिति को बदल दी है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांतवाद जैसे भावनात्मक मुद्दों के स्थान पर राष्ट्रीय राजनीति की बात कही है। श्री मोदी ने निवेश और विकास को राजनीतिक बहस में ऊपर रखा है। श्री मोदी ने राजनीति के केन्द्रीय मंच पर अर्थशास्त्र को गहरा स्थान दिया है और अन्य पार्टियों को इस नए मानक को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है।

सर्जिकल स्ट्राइक और डिमॉनेटाइजेशन के लिए मोदी सरकार ने दो परिभाषात्मक पहल की हैं। पहली स्थिति ने पाकिस्तान को अपनी पोषित रणनीति को बाहर कर दिया है। आज पाकिस्तान अपने ही रूख से तबाह माना जाता है जिससे अमरीका ने सहायता में 60 प्रतिशत की कटौती कर दी है। अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत को आतंकवाद का शिकार माना है। पिछले तीन वर्षों में श्री मोदी ने सभी प्रकार के आतंकी हमलों का सामना किया है और काश्मीर से सीमा पार झगड़ों के आतंक को सीमित रखा है जो कोई मामूली उपलब्धि नहीं कही जा सकती है।

नोटबंदी करके मोदी एक महान परिवर्तक के रूप में उभरे हैं और इस तरह अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। पिछले छह महीनों में यह क्रांतिकाल न केवल लगभग पीड़ाहीन रहा है, बल्कि श्री मोदी के कथनानुसार कठिन परिश्रम ने 'हार्वर्ड' पर विजय प्राप्त की है। आज भारत 7.9 दर से

श्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सर्वथा उत्कृष्ट दिखाई पड़ी है। उनकी सरल जीवनशैली, राष्ट्रनिर्माण के प्रति निःस्वार्थ भक्ति ने पार्टी के लिए इतनी अधिक राजनीतिक आस्था पैदा की है, जिसने अब तक के सर्वाधिक युवा और प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया है। अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता मोदी को पार्टी विचारधारा का प्रतीक तथा लक्ष्य मानते हैं। पार्टी की तरह ही राष्ट्र श्री मोदी के नेतृत्व में एक कल्याणकारी दिशा की तरफ बढ़ रहा है।

बढ़ रहा है जबकि विश्व 3.1 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहा है। 28 वर्षों में पहली बार 'मूडी' ने चीन की रेटिंग घटाई है। आर्थिक मोर्चे पर भारत एक चमकता सितारा है। सेंसेक्स नई ऊंचाईयां छू रहा है, मुद्रास्फीति नीचे की ओर जा रही है और लैण्डिंग उभार पर है। श्री मोदी के 'स्टार्ट अप' और 'मेक इन इंडिया मिशन नई तकनीक और निवेश ला रहे हैं, जिससे भारत की संभावनाएं एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बढ़ रही है।

श्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सर्वथा उत्कृष्ट दिखाई पड़ी है। उनकी सरल जीवनशैली, राष्ट्रनिर्माण के प्रति निःस्वार्थ भक्ति ने पार्टी के लिए इतनी अधिक राजनीतिक आस्था पैदा की है, जिसने अब तक के सर्वाधिक युवा और प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित किया है। अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता मोदी को पार्टी विचारधारा का प्रतीक तथा लक्ष्य मानते हैं। पार्टी की तरह ही राष्ट्र श्री मोदी के नेतृत्व में एक कल्याणकारी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय प्रकाशन विभाग के सदस्य हैं।)

स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का बड़ा अभियान

अनुपमा ऐरी

पिछले तीन वर्षों के दौरान नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों में व्यापक स्तर पर हुई वृद्धि भारत के ऊर्जा मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत ने पहले ही नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विशेषरूप से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की तरक्की ने देश को दुनिया के ऊर्जा नक्शे पर विशेष पहचान दिलाई है। वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में हाल ही में भारत की ऊर्जा क्षमता में परमाणु ऊर्जा के रूप में 7 गीगा वॉट (7000 मेगा वॉट) ऊर्जा क्षमता को शामिल किए जाने का निर्णय, जो एक ही बार में भारत के घरेलू परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कि दिशा में सबसे बड़ी मंजूरी, एक स्थायी रूप से कम कार्बन विकास रणनीति की दिशा में भारत की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता 6.7 गीगा वॉट (अथवा 6780 मेगा वॉट) है और 700 मेगावॉट प्रति रिएक्टर की क्षमता वाले 10 नए परमाणु रिएक्टरों को मंजूरी भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर और मज़बूत करेगा। 6.7 गीगा वॉट (6700 मेगा वॉट) की अन्य परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 2021-22 तक इनके परिचालन में आने की उम्मीद है।

घरेलू कंपनियों को करीब 70,000 करोड़ रुपये के संभावित विनिर्माण का कार्य मिलने के साथ ही, इस परियोजना से भारतीय परमाणु उद्योग में बड़े बदलाव के लिए मदद मिलने और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 33,400 से अधिक नौकरियां सृजित होने का अनुमान है।

नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर, आंकड़े अपने आप सफलता बयां करते हैं...

वर्ष 2014 में केन्द्रीय विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जब महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र की बागडोर संभाली, उस समय भारत में सौर ऊर्जा क्षमता केवल 2.65 गीगा वॉट (अथवा 2,650 मेगा वॉट) थी। एनडीए सरकार के तीन वर्ष पूरे करने पर, तीन वर्ष के भीतर ही भारत की सौर ऊर्जा क्षमता अभूतपूर्व तरीके से 4.5 गुणा बढ़कर 12.2 गीगा वॉट (अथवा 12,200 मेगा वॉट) पर पहुंच गई है।

यहां एक अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसका जिक्र किया जाना महत्वपूर्ण है, वह है सौर ऊर्जा की दरें। वर्ष 2014 में सौर ऊर्जा की दर 13 रुपये प्रति यूनिट से भी अधिक थी, जो वर्तमान में 500 मेगावॉट की क्षमता वाले राजस्थान के भाड़ला सौर पार्क की नीलामी में ऐतिहासिक रूप से कम होकर 2.44 रुपये प्रति यूनिट के निम्न स्तर पर पहुंच गई हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड स्तर है।

यह विश्व बैंक बिजली सुगमता रैंकिंग में 2014 के 99वें स्थान से वर्तमान में 23वें स्थान पर पहुंचने वाले भारत के लिए किसी भी मानक के अनुसार सराहनीय उपलब्धि है।

दिलचस्प बात यह है कि सौर ऊर्जा आज भारत में ताप और

कोयला आधारित ऊर्जा से भी सस्ती हो गई है, जबकि एक समय में ताप और कोयला ऊर्जा भारत के ऊर्जा क्षेत्र के आधार रहे हैं। यहां तक कि भारत की सर्वाधिक ऊर्जा सृजन कंपनी-एनटीपीसी की ऊर्जा की औसत लागत, सौर ऊर्जा के मोर्चे पर हासिल किए की गई उपलब्धियों से अधिक है।

उद्योग जगत और विशेषज्ञों के बीच उठे संदेहों को दूर रखते हुए, ऊर्जा की कम दरों की स्थिरता के बारे में केन्द्रीय विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि "पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने जब भी कम कीमतें तय की, हमने कीमतों के अनिश्चित स्तर के बारे में सुना। हमने इसके बारे में 12 से 10 होने पर सुना, 10 से 8, 8 से 5 और आज जब हम 4 पर हैं, जब भी ये सुन रहे हैं।"

नवीकरणीय ऊर्जा की दरों में इस गिरावट से उत्साहित, केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल को विश्वास है कि जल्द ही भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 60-65% हिस्सा हरित ऊर्जा का होगा। मंत्री श्री गोयल ने हाल ही में कहा कि "हम जिन दरों पर पहुंचे हैं, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आगामी दिनों में भारत की स्थापित क्षमता का 60-65 फीसदी हिस्सा हरित ऊर्जा का होगा।"

यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े ज़मीन आधारित सौर संयंत्र और दुनिया के सबसे बड़े छत आधारित सौर संयंत्र, दोनों ही भारत में हैं।

पवन ऊर्जा क्षमता के मोर्चे पर, भारत ने ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़कर पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में चीन, अमरीका और जर्मनी के बाद चौथा स्थान हासिल कर लिया है। सभी को सस्ती हरित ऊर्जा सुनिश्चित कराने के लिए भारत ने वर्ष 2016-17 में रिकॉर्ड 3.46 रुपये प्रति यूनिट की दर से 5.5 गीगावॉट की अतिरिक्त उच्चतम पवन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्य को हासिल किया है।

सौर, पवन, छोटी पनबिजली और जैव-शक्ति सहित भारत की नवीकरणीय क्षमता की बात करें, तो इन क्षेत्रों में पिछले तीन वर्ष में दो तिहाई की वृद्धि दर्ज की गई है, जोकि 35 गीगावॉट से बढ़कर 57 गीगावॉट पर पहुंच गई है। सरकार वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट सौर और 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। वर्ष 2022 तक भारत में कुल 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा सृजन की परिकल्पना की गई है।

वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 में मौजूद सौर ऊर्जा क्षमता की तुलना 370 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2014 में 2621 मेगावॉट से बढ़कर वर्तमान में मार्च 2017 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 12,277 मेगावॉट पर पहुंच गई है। इसी प्रकार, मार्च 2017 के अनुसार पवन ऊर्जा में भी 52 फीसदी की असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में 21,042 मेगावॉट पवन ऊर्जा की तुलना में मार्च 2017 में बढ़कर यह 32,304 मेगावॉट हो गई है। इसी अवधि के दौरान छोटे हाइड्रो पावर और जैव-ऊर्जा के क्षेत्र में प्रत्येक में 14% वृद्धि हुई है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तीन प्रमुख सुधारों का सारांश निम्नानुसार किया जा सकता है:

पवन क्षेत्र – यह क्षेत्र निश्चित टैरिफ व्यवस्था से प्रतिस्पर्धी बोली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिससे बिजली की लागत 20 फीसदी तक कम हो सकती है। सौर पार्कों के जरिए प्लग एंड प्ले मॉडल का प्रयोग कर सौर ऊर्जा सस्ती हो चुकी है और इसकी दरें 75 फीसदी से भी अधिक कम हो गई हैं और तीसरा अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के गठन के जरिए दुनिया में सौर क्रांति का नेतृत्व कर भारत ने जगतगुरु का खिताब पुनः प्राप्त किया है।

ग्रामीण भारत में, इस कैलेंडर वर्ष के अंत (दिसंबर 2018 तक के अपने लक्ष्य को खारिज करते हुए) तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का सरकार का कार्यक्रम तीव्र गति से चल रहा है। इस दिशा

वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 में मौजूद सौर ऊर्जा क्षमता की तुलना 370 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2014 में 2621 मेगावॉट से बढ़कर वर्तमान में मार्च 2017 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 12,277 मेगावॉट पर पहुंच गई है। इसी प्रकार, मार्च 2017 के अनुसार पवन ऊर्जा में भी 52 फीसदी की असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में 21,042 मेगावॉट पवन ऊर्जा की तुलना में मार्च 2017 में बढ़कर यह 32,304 मेगावॉट हो गई है। इसी अवधि के दौरान छोटे हाइड्रो पावर और जैव-ऊर्जा के क्षेत्र में प्रत्येक में 14% वृद्धि हुई है।

में सौर ऊर्जा के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक ग्रामीण इलाकों में बिजली की अनुपस्थिति में छात्रों को पढ़ाई करने में सक्षम बनाने के लिए इस कार्यक्रम के तहत करीब 10 लाख सौर लैंप छात्रों को वितरित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, सौर पंप स्थापित करके किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, पिछले तीन वर्षों में इस सरकार की एक अन्य प्रमुख उपलब्धि है। जहां एक ओर मार्च 2014 तक करीब 11,000 सौर पंप स्थापित किए गए थे, वहीं अब इन सौर पंपों की संख्या 1.1 लाख पहुंच गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार ने इस क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से करीब 9 गुणा अधिक संख्या में सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल किया है। ■

(पीआईबी)

सुधरती सत्ता, बिखरता विपक्ष

| प्रभात झा |

लोकतंत्र रूपी रथ के दो पहिए होते हैं- एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष। विपक्ष, सत्ता पर नियंत्रण के लिए होता है और विपक्ष का कमजोर होना सत्ता के बेलगाम होने की आशंका को जन्म देता है। आजादी के बाद भारत में सत्ता की दुर्दशा तो लोगों ने देखी थी विपक्ष की नहीं। आज तो देश का विपक्ष दुर्दशा के मुहाने पर खड़ा है। आजादी के बाद कुछ वर्षों को छोड़ दें तो कांग्रेस येन-केन-प्रकारेण केंद्र और राज्य की सत्ता में सदैव बनी रही।

इस दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्ष बिखर गया हो। वर्ष 1975 का दौर याद करें। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर कांग्रेस के नेताओं को छोड़ सभी नेताओं को अकारण जेल में ठूंस दिया था। ऐसे समय में भी जेल में विपक्षी एकता का जन्म हुआ और जनता पार्टी का गठन हुआ। वर्ष 1977 के आम चुनाव में इस विपक्षी एकता से न केवल इंदिरा गांधी की सत्ता गई, बल्कि कांग्रेस बहुत छोटी संख्या पर आकर टिक गई। लोकतंत्र में जितना अधिकार सत्ता पक्ष का होता है उतना ही विपक्ष का भी होता है।

मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, श्रीपद अमृत डांगे, ज्योति बसु, हिरेन मुखर्जी और इंद्रजीत गुप्त सरीखे नेता विपक्ष के नेता के रूप में ही स्थापित हुए। ये कम संख्या के बावजूद सत्ता पक्ष पर नैतिक नियंत्रण रखते थे। संसद के भीतर एक बार बहस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा था 'हम आपकी विचारधारा को कुचल देंगे। तब जनसंघ के अध्यक्ष डॉ. मुखर्जी ने जवाब में कहा था कि 'हम उस मानसिकता को कुचल देंगे जो हमारी विचारधारा को कुचलना चाहता है। नेहरू इस जवाब से हतप्रभ रह गए थे।

आज से 15-20 साल पहले सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के भाषण उनकी मर्यादा में चार चांद लगाते थे। चिंता की बात यह है कि आज ऐसा नहीं हो रहा। पहले सत्ता देश के लिए काम करती थी, वहीं विपक्ष भी देश के लिए सदन में आवाज बुलंद करता था। आज के हालात बदले हैं। केंद्र में जो सत्ता में हैं वह रोज संभल कर चल रही है और विपक्ष रोज बिखरकर कमजोर होता जा रहा है। सारे विपक्षी दल अपने ही दल के प्रमुख लोगों के आरोपों के नीचे दब गए हैं। देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि गत तीन वर्षों में जितने भी चुनाव हुए अधिकांश जगह पराजित हो गई।

एक-एक कर अनेक राज्यों में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं तीन साल पहले हुए आम चुनाव में लोकसभा में उसके मात्र 44 सदस्य जीतकर आए। उसकी हालत यह हो गई कि वह मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के रूप में भी नहीं रही। सब जानते हैं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जगह कोई दूसरा नेतृत्व होता तो कब का ही हटा दिया जाता। आज किसी से भी पूछो कि सोनिया जी के बाद कौन, तो हर कोई कांग्रेस में राहुल गांधी का ही नाम लेगा। कमोबेश यही स्थिति अन्य विपक्षी दलों की भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बिहार में राजद। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो या ओडिशा में बीजू जनता दल।

यहां तक कि पंजाब और महाराष्ट्र के दल और दिल्ली की राज्य सत्ता से जुड़े लोग अपनी ही पार्टी के नेताओं की मार से घायल हो रहे हैं। परिवारवाद की भेंट चढ़ रहा विपक्ष न तो देश का भला कर पा रहा है और न ही अपने दल का। परिवार और पार्टी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पार्टी देश के लिए काम करती है और परिवार में मात्र परिवार के लिए काम होता है। राजनीति में में नेताओं के प्रतिभावान और दल से जुड़े बच्चे या उनके परिवार के अन्य सदस्य नहीं आएं ऐसा कोई नहीं चाहेगा।

लेकिन दिक्कत तब होती है जब बिहार में लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं तो अपनी पार्टी के विधायकों में से किसी पर विश्वास न करते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना जाते हैं। दूसरी ओर उत्तर

नैतिक रूप से कमजोर विपक्ष कैसे बलवान हो सकता है। इस सवाल का जवाब तो विपक्षियों को ही तलाशना होगा। अन्यथा परिवारवाद के आगोश में लिपटे ये विपक्षी 'दल-दल में फंसे रहेंगे।

प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री का पद अखिलेश यादव को सिर्फ इसलिए सौंप देते हैं कि वह उनका पुत्र है। इतना ही नहीं बसपा, सपा, एनसीपी, राजद, बीजद सहित अनेक दल ऐसे हैं, जिनमें कार्यकर्ताओं का महत्व शून्य नजर आता है। जब विपक्षी दलों की हालत ऐसी हो वह भला केन्द्र में नरेंद्र मोदी की नैतिकता आधारित सरकार पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? हमें देखना होगा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होता है यही यदि परिवार आधारित हो जाएं तो अंतर्कलह बढ़ते देर नहीं लगती।

कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर आज लगभग सभी विपक्षी पार्टियां अतर्कलह की कगार पर हैं। पहले विपक्ष आगाह करता था तो सत्ता पक्ष चेत जाया करता थी। आज विपक्षी दिन भर सदन में हल्ला करते हैं फिर भी जनता उनके साथ न सड़क पर खड़ी है न संसद में। ऐसे में लोकतंत्र में आत्मावलोकन सभी दलों को करते रहना चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। नैतिक रूप से कमजोर विपक्ष कैसे बलवान हो सकता है। इस सवाल का जवाब तो विपक्षियों को ही तलाशना होगा। अन्यथा परिवारवाद के आगोश में लिपटे ये विपक्षी 'दल-दल में फंसे रहेंगे। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद हैं)

प्रधानमंत्री की जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 मई से 3 जून के दौरान यूरोप के चार देश- जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की सफल यात्रा की। छह दिनों की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने इन देशों के साथ आतंकवाद से निपटने, व्यापार और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की और कई महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने इन देशों को भारत में पूंजी निवेश के लिए भी आमंत्रित किया।

भारत–जर्मनी के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत-जर्मनी अंतर सरकारी वार्ता (चौथे चरण) के लिए 30 मई को बर्लिन पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह जर्मनी की दूसरी द्विपक्षीय यात्रा है। चांसलर एंजेला मार्केल ने बर्लिन के बाहरी इलाके में स्थित श्लॉस मेसेबर्ग में प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए अनौपचारिक रात्रिभोज का आयोजन किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब तीन घंटे तक विचार-विमर्श हुआ और समान हित वाले विभिन्न मुद्दों जैसे स्मार्ट शहर, कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा आदि पर चर्चा हुई। जीएसटी सहित भारत के विभिन्न आर्थिक सुधार एजेंडों को लेकर प्रशंसा मिली। गौरतलब है कि दोनों देशों ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

इन नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यूरोपीय संघ में एकजुटता के महत्व को दोहराया और दुनिया में स्थिरता के बल के रूप में इसके महत्व को रेखांकित किया। अफगानिस्तान के मसले पर दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के नेतृत्व वाली अफगान स्वामित्व वाली सुलह प्रक्रिया के महत्व को दोहराया। चर्चाओं में उथल-पुथल और आतंकवाद जैसे मुद्दे सामने भी आए। विचार-विमर्श के दायरे में चीन के वन बेल्ट, वन रोड और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी सामने आए।

जर्मनी और भारत 'एक दूसरे के लिए' बने: मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने 30 मई को बर्लिन में चौथे चरण की भारत-जर्मनी अंतर सरकारी वार्ता (आईजीसी) की सह-अध्यक्षता की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यूरोप और पूरी दुनिया को लेकर चांसलर मार्केल के नजरिये की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में आई नई गति साफ रूप से झलक रही है। उन्होंने कहा कि जर्मनी का भारत में विदेशी निवेश, खासकर मेक इन इंडिया को लेकर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 'वैश्विक मानक' पर जर्मनी के मापदंडों पर स्किल इंडिया मिशन के लिए उसकी साझेदारी महत्वपूर्ण है, जो भारत के लिहाज से खासी अहम है।

प्रधानमंत्री ने जलवायु संरक्षण और स्मार्ट शहरों जैसे विषयों के बारे में बात की, जो चर्चा के केंद्र में भी रहे। उन्होंने कहा कि जर्मनी का नवप्रवर्तन और भारतीय युवा स्टार्ट-अप अंतरिक्ष के क्षेत्र में गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र पर आधारित एक वैश्विक व्यवस्था और अन्योन्याश्रित दुनिया की आवश्यकता है।

सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्मनी और भारत 'एक दूसरे के लिए' बने हैं। उन्होंने जर्मन क्षमताओं और भारतीय आवश्यकताओं के बीच मौजूद विशाल तालमेल के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता में भारत की खोज की बात की। नवाचार और लोकतंत्र के मूल्यों को मानव जाति के लिए आशीर्वाद के रूप में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी इन मूल्यों को साझा करते हैं।

भारत और स्पेन के बीच हुए सात समझौते

स्पेन और भारत के बीच 31 मई को सात बड़े समझौते किए गए। इनमें सिविल एविशन, साइबर सुरक्षा, गैर पारंपरिक उर्जा, अंग प्रत्यारोपण

जैसे करार बेहद अहम हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मैड्रिड में राष्ट्रपति श्री मैरिएन राहोय के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा कि आज की वार्ता दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दूसरे पर आधारित और अन्योन्याश्रित दुनिया में स्पेन और भारत पारस्परिक लाभ के लिए एक साथ काम कर सकते हैं और इससे बड़े पैमाने पर दुनिया को लाभ मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रपति राहोय को दूरदर्शी नेता बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन दोनों ने आतंकवाद की समस्या का सामना किया है और दोनों देश ही इससे लड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और स्पेन दोनों जोरदार आर्थिक सुधारों में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, रेलवे और स्मार्ट शहरों में सहयोग के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत और स्पेन के बीच संबंधों में "नई गति" के माध्यम से "नए भारत" के विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच सात समझौते हुए, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा और नागरिक उड्डयन जैसे विषय शामिल हैं।

बाद में प्रधानमंत्री ने स्पेन की कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से मुलाकात की। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि भारत में स्पेनिश निवेश की और उसकी वृद्धि के लिए बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो, रसायन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने स्मार्ट शहरों की पहल में स्पेनिश भागीदारी को आमंत्रित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जीएसटी सहित भारत में किए गए आर्थिक सुधारों का व्यापक अवलोकन भी प्रस्तुत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया जैसे पहल निवेश के लिए वैश्विक मैग्नेट बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने उनके महामहिम राजा फेलिप छठवें से भी मुलाकात की।

कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भारत–रूस के बीच बड़ा सौदा

भारत और रूस ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देते हुए 1 जून को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दो और इकाइयां स्थापित करने और भारत से कीमती रत्नों तथा आभूषणों का निर्यात बढ़ाने समेत पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

इनमें कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में तीसरे चरण के दौरान पांचवीं और छठी इकाई के निर्माण के लिए समझौता, भारत से रूस को कीमती रत्नों एवं आभूषणों का निर्यात बढ़ाने के अलावा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदन-प्रदान बढ़ाने, नागपुर-सिकंदराबाद सेक्शन पर तीव्र गति की रेल सेवा के संबंध में समझौता और पारंपरिक ज्ञान की भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी में रूसी विशेषज्ञों पहुंच सुनिश्चित करने का समझौता शामिल है।

साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जून को सेंट पीटर्सबर्ग में 18वीं वार्षिक भारत-रूस शिखरवार्ता में रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादीमिर पुतिन से मुलाकात की। शिखरवार्ता के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच रक्षा से लेकर संस्कृति तक के विषयों पर अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक विषयों पर उल्लेखनीय तालमेल रहा है।

प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सहयोग का उल्लेख भारत और रूस के बीच संबंध के स्तंभ के रूप में किया और इस बात पर गौर किया कि आज की गई वार्ता और लिए गए निर्णयों से परमाणु, हाइड्रोकार्बन तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग और अधिक मजबूत होगा। इस संबंध में उन्होंने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 5 और 6 यूनिटों के समझौते का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक रिश्तों

को बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारत और रूस वर्ष 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत के लक्ष्य को पूरा करने के काफी करीब हैं। कनेक्टिविटी के विषय पर बोलते हुए प्रधान मंत्री ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कोरिडोर में दोनों देशों के बीच सहयोग का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 जून को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के समापन सत्र को संबोधित किया। समापन सत्र का विषय था- 'एचीविंग अ न्यू बैलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज' यानी वैश्विक स्तर पर नया संतुलन हासिल करना। भारत एसपीआईईएफ में इस साल 'अतिथि देश' है और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी 'गेस्ट ऑफ ऑनर' हैं।

भारत-रूस संबंधों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत कम संबंध हैं, जहां रिश्ते परस्पर विश्वास पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों से भारत-रूस संबंध विश्वास पर आधारित है और बदलती दुनिया में और भी अधिक मजबूत हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एसपीआईईएफ में वह 1.25 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसलिए भारत पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार सभी मोर्चों पर प्रगतिशील निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि आज हमारी वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत है।

प्रधनमंत्री श्री मोदी ने कहा कि 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' और 'रेड टेप के बजाय रेड कारपेट' भारत में शासन सुधारों का आधार रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और स्पष्ट दृष्टिकोण सुधार के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि अफसरशाही भी जीवंत और नेतृत्व के अनुरूप होनी चाहिए।

विविधता ही भारत की ताकत है, का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर लागू होने जा रहा है और इससे पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति पुतिन, जिन्होंने उनसे पहले संबोधित किया था, से सहमति जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी अब एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है और उन्होंने इस संदर्भ में डिजिटल इंडिया अभियान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 'डिजिटल डिवाइड' को समाज में जड़ जमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेशीकरण के लिए सरकार के कार्यक्रमों- जनधन, आधार, मोबाइल (जेएएम) ट्रिनिटी का उल्लेख किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 1200 से अधिक कानूनों को खत्म करने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कारोबारी सुगमता के लिए महज केंद्र सरकार के स्तर पर 7000 सुधार किए हैं।

प्रधानमंत्री ने एफडीआई और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने एफडीआई के लिए भारत को शीर्ष तीन जगहों में से एक के रूप में पहचान की है। निवेशकों के लिए सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जीवंत लोकतंत्र और अंग्रेजी का इस्तेमाल सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होगा।

पेरिस जलवायु समझौता पूरी दुनिया की साझी विरासत: मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों से पेरिस में मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित

करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अपने जोरदार स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने मानवता और मानवीय मूल्यों की सेवा के बारे में बताते हुए कहा कि वर्षों से फ्रांस-भारत के संबंध आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगे भी यह संबंध इसी तरह कायम रहेंगे।

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अतंरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की तरफ ध्यान दिलाया और कहा कि भारत और फ्रांस दिशा में संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पेरिस जलवायु समझौते को पूरी दुनिया की साझी विरासत बताया और उम्मीद जताई कि यह अगली पीढ़ी के लिए उम्मीद की नई किरण बनेगा। उन्होंने कहा कि धरती माता को बचाने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने राजनीतिक यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पेरिस शहर का वर्णन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फ्रांस ने इस समझौते के लिए कंधे पर कंधे से काम किया था। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारतीयों के विश्वास सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा का हिस्सा बताया ।

उन्होंने कहा कि भारत समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। इससे आगे भी वह दूसरों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि भविष्य के पीढ़ियों के लिए एक उपहार प्रदान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद और कट्टरपंथियों का मुकाबला करने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत एक संयुक्त प्रगतिशील यूरोपीय संघ के पक्ष में है। ■

भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित

भाजपा किसान मोर्चा ने 8 जून को अपनी नयी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी। कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, दो महासचिव, आठ सचिव एक कोषाध्यक्ष एवं 50 कार्यकारिणी सदस्य होंगे।

भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची:

अध्यक्ष – श्री बीरेन्द्र सिंह 'मस्त'

राष्ट्रीय प्रभारी – श्री सतपाल मलिक

राष्ट्रीय संगठक – श्री हृदयनाथ सिंह

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष – श्री ए. पासा पाटिल, (महाराष्ट्र)
– श्री ओमप्रकाश यादव, सांसद, (बिहार)
– सावित्री ठाकुर जी, सांसद (मध्य प्रदेश)
– श्री नरेश सिरोही (उत्तर प्रदेश)
– श्री शैलेंद्र सेंगर (बिहार)
– श्री शंकर गौर पाटिल (कर्नाटक)
– श्री महेश्वर साहू (ओडिशा)
– श्री अजीत चौबे (उत्तर प्रदेश)

महामंत्री – श्री पी. सुग्राकर राव (तेलंगाना)
– श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, सांसद (राजस्थान)

राष्ट्रीय मीडिया कम्युनिकेटर– श्री राकेश सिंह (उत्तर प्रदेश)

कोषाध्यक्ष– श्री सुधीर त्यागी (उत्तर प्रदेश)

राष्ट्रीय मंत्री – श्री प्रवीण पटेल, विधायक (उत्तर प्रदेश)
– श्री शम्भू कुमार (बिहार)
– श्री ओमप्रकाश यादव (मध्य प्रदेश)
– श्री पी.सी. मोहनन मास्टर (केरल)
– श्री दिनेश त्यागी (हरियाणा)
– श्री सुखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल (पंजाब)
– श्री दुष्यंत लाकरा (दिल्ली)
– श्री राजेश सेंगर (मध्य प्रदेश)

समन्वयक– (केंद्र व राज्य सरकार) श्री मंजीत सिंह (दिल्ली) ■

भारत और कोरिया के बीच एमओयू को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीसरे देशों की परियोजनाओं के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति और भारत में बुनियादी ढांचागत विकास के लिए 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात ऋण के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) और कोरिया के निर्यात-आयात बैंक (केईएक्सआईएम) के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी है।

वार्षिक वित्तीय द्विपक्षीय वार्ता के लिए 14-15 जून 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली की आगामी सोल, कोरिया यात्रा के दौरान दोनों बैंकों के बीच इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। इस निर्णय से देश के अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा मिलने और भारत एवं कोरिया के बीच राजनीतिक एवं वित्तीय संबंधों में गहराई आने की उम्मीद है। निर्यात ऋण का उपयोग तीसरे देशों की परियोजनाओं तहत भारत और कोरिया से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के साथ-साथ भारत में स्मार्ट सिटी, रेलवे, बिजली उत्पादन एवं पारेषण आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक से ऋण के जरिये किया जाएगा। कार्यान्वयन रणनीति के तहत इस एमओयू के सभी पक्ष वित्तीय सहायता का ढांचा तैयार करने, मौजूदा व्यवस्थाओं एवं संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए आपस में विचार-विमर्श करेंगे। एग्जिम बैंक भारत में व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करेगा। तीसरे देशों में परियोजनाओं के लिए दोनों पक्ष संयुक्त रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करेंगे।

एग्जिम बैंक से पता चला है कि निवेश ऋण (विशेष रूप से कोरियाई आयात सामग्री के एक निश्चित स्तर और ओईसीडी के निर्यात ऋण दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दरों के साथ परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए निर्यात ऋण सुविधा) के तौर पर केईएक्सआईएम 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएगा। केईएक्सआईएम द्वारा इस रकम का उपयोग एग्जिम बैंक की भागीदारी के बिना ऋणदाता के तौर पर भी किया जा सकता है जो उसकी संतुष्टि पर निर्भर करेगा। तीसरे देशों की परियोजनाओं के तहत भारत और कोरिया से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत पैदा होगा जो इस एमओयू की वजह से संभव हो सकेगा। यह पारस्परिक अनुभव का आदान-प्रदान करने, निर्यात एवं आयात कारोबार पर वित्त पोषण संबंधी जानकारी साझा करने, परियोजनाओं का आकलन करने और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में ज्ञान के सृजन में मदद करेगा। ■

1.17 करोड़ से अधिक लोगों का कौशल विकास

कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी ने 6 जून को कहा कि स्किल इंडिया कार्यक्रम के आरंभ से मंत्रालय ने 1.17 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीएम) की योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया। यह संख्या अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के अधीन कौशल विकास योजना के अंतर्गत चलाये जाने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं के अतिरिक्त है।

श्री रुडी ने कहा कि स्किल इंडिया एक मूक क्रांति है, जो जारी है। सरकार देश के भविष्य के विकास के लिए निजी साझेदारों के साथ मिलकर यह संयुक्त निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर सावधानी से कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि इसमें हमारे देश के युवाओं का भविष्य शामिल है। उन्होंने कहा कि आज जो हम बोएंगे, वहीं हम कल काटेंगे। इसीलिए हमने पहले 2 वर्ष का समय सही आधारशिला तैयार करने में लगाया, ताकि कौशल पर्यावरण का अपनी कौशल योग्यताओं के राष्ट्रीय मानकों के साथ मेल करा सके।

श्री रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जिसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। अकेले इसके अंतर्गत 26.5 लाख लोगों को उनके चयनित कौशल क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 50 प्रतिशत महिला प्रत्याशी रही।

उन्होंने कहा कि यह देखकर सुखद अनुभव होता कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कौशल प्राप्त करने के लिए आगे आ रही हैं। पिछले वर्ष पीएमकेवीवाई के अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता 40 प्रतिशत थी। मंत्री ने कहा, "मैं यह देखकर प्रफुल्लित हो रहा हूं कि इस वर्ष हमारा महिला-पुरूष अनुपात बढ़कर समान हो गया।"

श्री रूडी ने कहा, "निजी/उद्योग क्षेत्र तभी साझेदार बनेगा] जब उसे स्किल इंडिया के माध्यम से कुशल कार्यबल मिलता हुआ दिखाई देखा। हमें यह बदलाव धीरे-धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है। विभिन्न स्तरों पर ज्यादा से ज्यादा कार्पोरेट हमारे साथ साझेदारी कर रहे हैं। चाहे यह नौसिखियों को प्रशिक्षण देने की बात हो, अवसंरचना को प्रोत्साहन देना हो, सीएसआर निधियों के माध्यम से योगदान हो या फिर पारिश्रमिक संसाधनों को चुनने का विषय हो।"

जालसाजी और ठगी की निगरानी पर किए गए सवाल के जवाब में श्री रूडी ने कहा, "कुछ मुटठी भर संस्थायें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एजेंसियां होने का दावा करती हैं और भोले-भाले लोगों से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीएम) के नाम पर पैसे लेने और बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के झूठे दावे करती हैं। इस तरह के ज्यादातर विज्ञापन क्षेत्रीय समाचार पत्रों में पाये जाते हैं। हम इस तरह के कृत्यों की निंदा करते हैं और

उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवाते हैं।" उन्होंने जनता को चेताया कि लोगों को इस तरह की धोखा देने वाली संस्थाओं से सचेत रहना चाहिए और इनसे जुड़ने से पहले इनकी संबद्धता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीएम) सचिव श्री के पी कृष्णन ने कहा कि भारत के संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में वर्णित 52 विषयों में से व्यावसायिक शिक्षा एक बिंदु है। इसका अर्थ यह भी है कि मुख्य रूप से राज्यों को ही इस आदेश को राज्य भर में केंद्र के सहयोग से चलाना होगा। केंद्र का सहयोग निधि, राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण के रूप में होगा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीएम) ने राज्य कौशल विकास मिशनों के साथ मिलकर अल्पकालीन प्रशिक्षणों को श्रेणीबद्ध करने का काम किया है और संकल्प जैसी विश्व बैंक की योजनाओं को भी राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों से जल्द ही अंतिम दूरी भी तय हो जाएगी।

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि वे आपूर्ति आधारित कौशल विकास परिदृश्य से दूर हटकर मांग आधारित की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं] ताकि भारत में कौशलयुक्त युवा बेरोजगार न रहे। गौरतलब है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 5 गुणा बढ़ोतरी हुई है। यह अप्रेंटसिशप एक्ट एनएपीएस में किये गए व्यापक सुधारों के परिणाम है। जिसमें सरकार उद्योगों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। एनएपीएस के अंतर्गत अभी तक 5.9 लाख लोग प्रशिक्षण में लगाया गया है। ■

2016-17 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात सबसे ज्यादा रहा

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फ्रोजन झींगा और फ्रोजन मछली की भारी मांग के मद्देनजर, भारत ने 2016-17 में अब तक का सबसे ज्यादा 5.78 अरब अमरीकी डॉलर (37,870.90 करोड़ रूपये) मूल्य का 11,34,948 मीट्रिक टन सीफूड का निर्यात किया, जो एक साल पहले 9,45,892 टन और 4.69 अरब डॉलर था। अमरीका और दक्षिण पूर्व एशिया लगातार सबसे ज्यादा आयात करने वाले देशों में रहे, जबकि यूरोपीय संघ से मांग में भी इस अवधि में इजाफा हुआ है।

फ्रोजन झींगा निर्यात किए जाने वाली चीजों में 38.28 प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर रहा। इससे 64.50 प्रतिशत (डॉलर में) कुल आय हुई। झींगा का निर्यात मात्रा में 16.21 प्रतिशत बढ़ा और डॉलर में 20.33 प्रतिशत। फ्रोजन मछली सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली चीजों में 26.15 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रही। इससे 11.64 प्रतिशत (डॉलर में) आय हुई। इसमें 26.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अमरीका ने 1,88,617 मीट्रिक टन भारतीय सीफूड का आयात किया, जो डॉलर में 29.98 प्रतिशत है। इस देश के लिए निर्यात में मात्रा, रूपये और अमरीकी डॉलर के संदर्भ में 22.72 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 29.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दक्षिण पूर्व एशिया 29.91 प्रतिशत के साथ (अमरीकी डॉलर में) भारत के समुद्री उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। इसके बाद यूरोपीय संघ (17.98 प्रतिशत), जापान (6.83 प्रतिशत), मध्य पूर्व (4.78 प्रतिशत) चीन (3.50 प्रतिशत) और अन्य देशों में (7.03 प्रतिशत) रहा। दक्षिण पूर्व एशिया में कुल निर्यात मात्रा में 47.41 प्रतिशत, आय में 52.84 प्रतिशत रुपये में और 49.90 प्रतिशत डॉलर में वृद्धि हुई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वानैमी के उत्पादन में वृद्धि, मत्स्यपालन प्रजातियों के विविधीकरण, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए निरंतर उपायों और मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि के कारण सीफूड के निर्यात में भारत की सकारात्मक वृद्धि हुई।

2016-17 के दौरान झींगा का कुल निर्यात 4,34,484 मीट्रिक टन रहा जिससे 3,726.36 मिलियन अमरीकी डॉलर आय हुई। अमरीका 1,65,827 मीट्रिक टन के साथ फ्रोजन झींगा के लिए सबसे बड़ा आयात बाजार रहा। इसके बाद यूरोपीय संघ (77,178 मीट्रिक टन), दक्षिण पूर्व एशिया (1, 05,763 मीट्रिक टन), जापान (31,284 मीट्रिक टन), मध्य पूर्व (19,554 मीट्रिक टन), चीन (7818 मीट्रिक टन) और अन्य देशों में (27,063 मीट्रिक टन) रहा।

2016-17 में प्रमुख समुद्री खाद्य व्यंजन वानैमी का निर्यात 2,56,699 मीट्रिक टन से बढ़कर 3,29,766 मीट्रिक टन हो गया, जिससे मात्रा में 28.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वैल्यू के संदर्भ में कुल वानैमी का 49.55 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किया गया। इसके बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 23.28 प्रतिशत, यूरोपीय संघ में 13.17 प्रतिशत, जापान में 4.53 प्रतिशत, मध्य पूर्व में 3.02 प्रतिशत और चीन में 1.35 प्रतिशत रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फ्रोजन झींगा और फ्रोजन मछली की भारी मांग के मद्देनजर, भारत ने 2016-17 में अब तक का सबसे ज्यादा 5.78 अरब अमरीकी डॉलर (37,870.90 करोड़ रुपये) मूल्य का 11,34,948 मीट्रिक टन सीफूड का निर्यात किया, जो एक साल पहले 9,45,892 टन और 4.69 अरब डॉलर था। अमरीका और दक्षिण पूर्व एशिया लगातार सबसे ज्यादा आयात करने वाले देशों में रहे, जबकि यूरोपीय संघ से मांग में भी इस अवधि में इजाफा हुआ है।

जापान 43.84 प्रतिशत के शेयर के साथ ब्लैक टाइगर झींगा के लिए सबसे बड़ा बाजार रहा। इसके बाद अमरीका (23.44) और दक्षिण पूर्व एशिया (11.33) था। फ्रोजन झींगा लगातार अमरीका को (94.77 प्रतिशत डॉलर मूल्य में) प्रमुख रूप से निर्यात किया गया जबकि वानैमी के निर्यात में 25.60 प्रतिशत मात्रा में और 31.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

76.57 प्रतिशत मूल्य (यूएस डॉलर) के शेयर के साथ वियतनाम, भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए प्रमुख दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार रहा। इसके बाद थाईलैंड (12.93 प्रतिशत), ताइवान (3.88 प्रतिशत), मलेशिया (2.60 प्रतिशत), सिंगापुर (2.21 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (1.50 प्रतिशत) और अन्य देशों (0.30 प्रतिशत) का रहा। अकेले वियतनाम ने 3,18,171 मीट्रिक टन भारतीय सीफूड का आयात किया, जो अमरीका, जापान और चीन जैसे किसी भी दूसरे बाजारों के मुकाबले काफी ज्यादा है।

यूरोपीय संघ 16.73 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए लगातार तीसरा सबसे बड़ा बाजार रहा। फ्रोजन झींगा सबसे ज्यादा निर्यात किया गया, जिसका यूरोपीय संघ के कुल निर्यात में 40.66 प्रतिशत मात्रा में व 55.15 प्रतिशत डॉलर आय में योगदान रहा। यूरोपीय संघ के लिए वानैमी के निर्यात मात्रा में 9.76 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में 11.40% की वृद्धि हुई।

जापान, भारतीय सीफूड के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार (6.83 प्रतिशत आय और 6.08 प्रतिशत मात्रा के मामले में) रहा। फ्रोजन झींगा जापान निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु रही जो कुल निर्यात का 45.31 प्रतिशत मूल्य में 77.29 प्रतिशत रहा।

फ्रोजन झींगा और फ्रोजन मछली के अलावा भारत के प्रमुख सीफूड उत्पाद फ्रोजन स्क्विड को बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया, जिसमें 21.50 प्रतिशत, 59.44 प्रतिशत और 57 प्रतिशत की वृद्धि क्रमशः मात्रा, रुपया मूल्य और डॉलर आय में हुई। हालांकि फ्रोजन कटलफिश के निर्यात मात्रा में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन रुपये के मूल्य में और डॉलर के संदर्भ में क्रमशः 18.85 और 16.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सूखी वस्तुओं में क्रमशः मात्रा, रुपया मूल्य और डॉलर के संदर्भ में 40.98%, 20.14% और 79.05% की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय बंदरगाहों ने 2015-17 में 11,34,948 टन कुल समुद्री माल, जिसका मूल्य 37,870.90 करोड़ (5,777.61 मिलियन अमरीकी डालर) था, का प्रबंधन किया। जबकि 2015-16 में यह 9,45,892 टन एवं मूल्य 30,420.83 करोड़ (4,687.94 मिलियन अमरीकी डालर) था। विजाग, कोच्चि, कोलकाता, पीपावाव और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपी) प्रमुख बंदरगाह थे जहां से 2016-17 के दौरान समुद्री माल का प्रबंधन किया गया। 2015-16 की तुलना में विजाग, कोच्चि, कोलकाता, पिपवव, जेएनपी, कृष्णपट्टनम और तुतिकोरिन से निर्यात में सुधार हुआ है।

वाइजैग बंदरगाह ने 2016-17 में 9,294.31 करोड़ रुपए (1,401.94 मिलियन अमरीकी डॉलर) मूल्य के 1,69,773 टन समुद्री कार्गो का निर्यात किया, जबकि 2015-16 में 7,161 करोड़ रुपये (1,105.76 मिलियन डॉलर) मूल्य के 1,28,718 टन का निर्यात किया गया था।

वाइजैग बंदरगाह के बाद कोच्चि (1,55,989 टन, 4,447.05 करोड़ रूपये), कोलकाता (1,04668 टन, 4,451.67 करोड़ रूपये), पीपावाव (2,32,391 टन, 4,217.45 करोड़ रूपये), जेएनपी (1,49,914 टन, 4,084.96 करोड़ रुपये) कृष्णापट्टनम (62,049 टन, 3,701.63 करोड़ रूपये), तुतिकोरिन (42,026 टन, 2,220.52 करोड़ रूपये) और चेन्नई (37,305 टन, 1,693.87 करोड़ रूपये) शामिल हैं। ■

'स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ' अभियान की शुरूआत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 6 जून को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु 'स्किल फोर लाइफ, सेव अ लाइफ' अभियान की शुरूआत की । इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भारत जन-सांख्यकीय लाभ की स्थिति में है, क्योंकि भारत की 65 फीसदी से अधिक आबादी 35 वर्ष की आयु से नीचे है। सरकार ने इस स्थिति में युवाओं को जरूरी कौशल देकर सतत और समेकित विकास की मजबूत आधारशिला रखना सुनिश्चित किया है। "स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ" अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में प्रशिक्षित लोगों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना है। इस अभियान तहत कई पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना है। जिसके तहत हैल्थ केयर के क्षेत्र में अलग-अलग योग्यताओं वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही आम लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव सी.के. मिश्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत में प्रतिनिधि डॉ. हेंक बेकेडम भी इस अवसर पर मौजूद थे।

समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि युवाओं के कुशल होने से उन्हें शीघ्र रोजगार मिलता है और इससे देश समृद्ध होगा। श्री नड्डा ने कहा कि इससे युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीदों वास्तविक नौकरियों की उपलब्धता के बीच अंतर कम होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि कुशलता से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती और प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित कुशल मानव संसाधन की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम होता है। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यापक संभावनाएं है। ऐसी पाठ्यक्रमों के शुरू होने से स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मी मिल सकेंगे। श्री नड्डा ने बताया कि सभी कोर्सों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान और अखिल भारतीय आर्युविज्ञान नई दिल्ली में तैयार किया है। ■

पूर्वोत्तर में पिछले 20 वर्ष में सबसे कम अलगाव की घटनाएं: राजनाथ सिंह

पिछले तीन वर्ष में वामपंथी उग्रवादियों के समर्पण में रिकॉर्ड 185 प्रतिशत वृद्धि

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 जून को कहा कि सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के लिये कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए विभिन्न प्रभावी उपाय किए हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान निरंतर सुरक्षा पहलों के कारण देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में दशकों के अलगाव के बाद शांति और स्थिरता आई है। इस क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों की तुलना में वर्ष 2016 में सबसे कम अलगाव की घटनाएं देखी गई हैं। वर्ष 2014 में उग्रवाद की 824 घटनाओं की तुलना में 2016 में 484 ऐसी वारदातें हुई। 2015 में 574 अलगाववाद घटनाएं हुई, जो 1997 के बाद से सबसे कम थी और 2016 में ऐसी घटनाएं और कम हो गई। पिछले तीन वर्ष में पूर्वोत्तर में मारे गये नागरिकों की संख्या भी काफी कम थी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों के अधिकार तथा पात्रता सुनिश्चित कर उनकी सुरक्षा और विकास करना है। इसके परिणाम स्वरूप मई 2011 से अप्रैल 2014 की तुलना में मई 2014 से अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी घटनाएं 25 प्रतिशत कम हुई और सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या में 42 प्रतिशत तक की कमी आई। इसके अलावा वामपंथी उग्रवादियों का सफाया करने में 65 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण में रिकॉर्ड 185 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 8 मई, 2017 को हुई वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक में वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक परिचालन सिद्धांत 'समाधान (एसएएमएडीएचए)' स्थापित किया। इस रणनीति के मूल में एस का अर्थ स्मार्ट पुलिस और नेतृत्व, ए मतलब आक्रामक (एग्रेसिव) रणनीति, एम यानी बढ़ावा (मोटीवेशन) और प्रशिक्षण, ए- कार्रवाई (एक्शनेबल) करने योग्य खुफिया जानकारी, डी मतलब डैशबोर्ड आधारित महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र और प्रमुख निष्पादन संकेतक, एच का अर्थ तकनीकी का उपयोग करना (हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी), ए मतलब प्रत्येक कार्रवाई के लिए कार्य योजना (एक्शन प्लान) और एन का अर्थ उन तक धन राशि नहीं पंहुची है।

मंत्री महोदय ने कहा कि सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की घटनाओं में 45 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। प्रधान मंत्री के विकास पैकेज (पीएमडीपी 2015) के तहत 63 प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिये 80,068 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं और 61,112 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गयी है। विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का पारितोषिक 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है और मौजूदा 25,474 एसपीओ के अलावा 10,000 अतिरिक्त एसपीओ की तैनाती की मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिये कई कल्याणकारी योजनाएं, कश्मीरी प्रवासियों के लिए पारगमन आवास, कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रति व्यक्ति 2500 रूपये और प्रति परिवार के लिये 10,000 रुपये तक की मासिक नकद राहत और जम्मू से विस्थापितों के लिये भी पहली बार ऐसी ही राहत राशि मंजूर की गई है। पांच नयी भारतीय रिजर्व बटालियनों को मंजूरी दी गई है और राज्य सरकार से कहा गया है कि वे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दें। अन्य राज्यों में पढ़ाई करने वाले जम्मू-कश्मीर के छात्रों की सहायता के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 10 वर्षों के अंतराल के बाद 16 जुलाई 2016 को अंतर राज्यीय परिषद की 11वीं बैठक आयोजित की गई थी। सरकार ने क्षेत्रीय परिषदों को भी पुर्नगठित किया और गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिषदों की 8 बैठकें हुईं, जिनमें 199 विषयों पर चर्चा की गई और 87 मुद्दों का समाधान किया गया।

2015 के वार्षिक डीजीपी सम्मेलन में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखी गई स्मार्ट नीति पहल के अनुरूप श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने लगभग 28,000 सर्वोत्तम तरीकों को ऑनलाइन साझा किया है, जिनका अन्य राज्य अनुकरण कर सकते हैं। अपराध और अपराधियों को पकड़ने का नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना का कार्य जल्दी ही संपन्न होने वाला है, जिसके तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) साझा करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि यह आंकड़ा मार्च 2014 में शून्य था। मार्च 2014 में सीसीटीएनएस का उपयोग कर कुल पंजीकृत एफआईआर की संख्या 1.5 लाख से भी कम थी जो लगभग 100 गुना बढ़कर 1.25 करोड़ हो गई।

मंत्री महोदय ने कहा कि सीमा पर बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले तीन वर्ष में 5,188 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से 2,138 करोड़ रुपये भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमा परियोजनाओं के लिए जारी किए गए हैं। इनमें 200 किलोमीटर की बाड़ लगाना, 430 किलोमीटर लंबी सीमा सड़कों का निर्माण, 647 किमी की सीमाओं पर फ्लडलाईट और 110 समग्र सीमा चौकी बनाना शामिल हैं। भारत-चीन सीमा के संबंध में 2008 में स्वीकृत 27 सीमावर्ती सड़कों में से 2014-16 की अवधि के दौरान पहली 8 सड़कें बन चुकी हैं, जबकि अन्य 9 सड़कों का कार्य इस साल के अंत तक संपन्न हो जायेगा।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आदर्श गांवों के निर्माण के लिए एक नई पहल की गई है। इसके लिए 7 राज्यों को 41 आदर्श गांव विकसित करने के लिए लगभग 92 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के 24 गांव शामिल हैं। सीमाओं पर व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) स्थापित करने को बढ़ावा दे रही है। जून 2016 में रक्सौल में और नवंबर 2016 में जोगबनी में आईसीपी शुरू की गयी थीं। पिछले साल जुलाई में भारत और बांग्लादेश के प्रधान मंत्रियों द्वारा आईसीपी, पेट्रोपोल में कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था और जनवरी 2017 में मेघालय के दावकी में एक आईसीपी की आधारशिला रखी गई थी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले तीन वर्ष के दौरान वैध विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए वीज़ा व्यवस्था को उदार, सरलीकृत और तर्कसंगत बनाया गया है। 162 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा बढ़ा दी गई है। ई-वीज़ा पर ठहरने की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। मार्च 2016 से जापान के नागरिकों के लिए वीजा-पर-आगमन योजना शुरू की गई है, जबकि बांग्लादेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहु प्रवेश पर्यटक वीजा की अवधि एक साल से बढ़ा कर पांच साल तक कर दी गई है।

मंत्री महोदय ने कहा कि भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आपदा प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जून 2016 में शुरू की गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना सेंडाई रूपरेखा के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को एकीकृत करने वाली दुनिया में पहली योजना है। भारत ने दिल्ली एनसीआर में पहले दक्षिण एशियाई आपदा प्रबंधन का अभ्यास किया और नवंबर 2016 में आपदा जोखिम को कम करने (डीआरआर) विषय पर 7वें एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें प्रधान मंत्री ने डीआरआर के लिए 10 सूत्री योजना की घोषणा की। सरकार ने वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में बेहतर कवरेज के लिए एनडीआरएफ की दो अतिरिक्त बटालियनें भी गठित की।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता रही है। मंत्रालय ने कांस्टेबल स्तर के 33 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती को मंजूरी दी है। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल स्तर के पदों के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण और सीमा सुरक्षा बलों यानी बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में कांस्टेबल स्तर के पदों के लिये 14-15 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू होंगे। सरकार राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था (एनईआरएस) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है, जिसे इस साल अक्टूबर में शुरू किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों की तुलना में वर्ष 2016 में सबसे कम अलगाव की घटनाएं देखी गई हैं। वर्ष 2014 में उग्रवाद की 824 घटनाओं की तुलना में 2016 में 484 ऐसी वारदातें हुई।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 अप्रैल, 2017 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वीरता दिवस के अवसर पर "भारत के वीर" नाम से वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया था। कर्तव्य निभाते हुये अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर सैनिकों के परिवार को योगदान देने वाले दाताओं के लिये यह पोर्टल एक आईटी आधारित मंच है। यहां दान की राशि उस केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल / केंद्रीय अर्ध सैन्य बल के सैनिक के 'निकटतम संबंधी' के खाते में जमा हो जाएगी, जिसके लिये दी गई है। पोर्टल पर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 मई, 2017 को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए गृह मंत्रालय का मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया। मोबाइल एप्लिकेशन में मंत्रालय के लिए कर्मियों की शिकायतों पर विभिन्न सीएपीएफ द्वारा की गई कार्रवाई पर लगातार नजर रखने तथा शिकायत निवारण प्रणाली में और सुधार की प्रक्रिया को नियमित करने के प्रावधान हैं। ■

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता					
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/- ☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/- ☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

जर्मनी, स्पेन, रूस एवं फ्रांस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रवास की छवियां

जर्मनी

स्पेन

रूस

फ्रांस

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश' सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003